

साप्ताहिक

शान्ति मिश्रा

नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 04

23 - 29 जनवरी 2022

पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

अजीजन बाई-उसकी पाजेब से निकलती थी क्रांति की हुंकार पृष्ठ-6

शहीद-ए-वतन के मज़ार पर फूलों की कैफियत पृष्ठ-7

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव-2022

वोटकूपने वोटकी अटमियत को समझें

लोकतंत्र में एक-एक वोट की बड़ी महत्ता होती है इसलिए अपना वोट अच्छे प्रत्याशी को देकर अपने देश का एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दें।

देश के पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य जो माना जा रहा है जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश। कई मायने में यह प्रदेश अनूठा है क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी जनसंख्या दुनिया के कई देशों की तुलना में छठे नंबर पर आती है परंतु इसके बड़े होने का एकमात्र कारण यही नहीं है क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रदेश के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर भारत की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री प्रायः इसी राज्य से चुनाव जीता है। इसी बजह से इस राज्य में आगामी 07 मार्च तक होने वाले चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पंजाब ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। तीसरी ओर उत्तराखण्ड ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी इलाक़ा माना जाता है और इसकी सीमाएँ भी चीन से जाकर मिलती हैं। चौथा राज्य गोवा ऐसा प्रदेश है जो 1960 तक पुरतगाल के शासन में रहा और समुद्री तट पर स्थित है। पांचवां राज्य मणिपुर है जो भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति का अनुपम उदाहरण है और पर्वतीय मनोरम छठाओं से भरा हुआ है।

पूर्वोत्तर के इस राज्य की सीमाएँ भी म्यामार को छूती हैं। एक प्रकार

से इन पांच राज्यों को हम भारत के विशाल स्वरूप का अंश प्रतिनिधि कह सकते हैं। अतः इन सभी राज्यों के चुनाव परिणामों का प्रभाव भारत की सकल राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। यदि हम इन सभी राज्यों की राजनीतिक बनावट को देखें तो यह विविध रूपों में दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध की जो तस्वीर उभर रही है उसमें सत्ताधारी पार्टी भाजपा का मुकाबला एक क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी से दिखाई पड़ रहा है और देश

अतः इन चुनावों को यदि हम संपूर्णता लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी कहें तो कोई गलत नहीं होगी क्योंकि राष्ट्रीय धरातल पर 2024 में भी यही राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना है। विचार करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे क्या रहते हैं। ये चुनाव हर राज्य में नई सरकार बनाने के लिए हो रहे हैं, अतः चुनावी मुद्रे भी राज्य स्तर के या क्षेत्रीय समस्याओं को उग्र तक बनाने के मुद्रे भी आ

को लेकर ही होने चाहिए।

जिस प्रकार भारत की संस्कृति विविधतापूर्ण है उसी प्रकार इसकी राजनीति भी विविधतापूर्ण है यही वही है कि राज्यों में सरकार अलग अलग दलों की बनती रहती है परंतु पिछले तीन दशकों से इसमें परिवर्तन आया है देखने में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल मतदाताओं को लुभाने के लिए वादा करने की हदें इस तरह पार कर जाते हैं जिनका तारतम्य जाकर भारत की संघीय व्यवस्था से नहीं जुड़ता। इस संबंध में क्षेत्रीय भावनाओं को उग्र तक बनाने के मुद्रे भी आ जाते हैं। साथ ही चुनावी वादा करते समय राजनीतिक दल अपने राज्य की वित्तीय व्यवस्था व संसाधनों की भी परवाह नहीं करते। अब तो इससे भी आगे मुफ्त सौगात तक बांटने के बादे होने लगे हैं।

की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। मगर पंजाब में सत्तारुद़ पार्टी कांग्रेस का मुकाबला बहुकोणीय नज़र आ रहा है। जबकि मणिपुर में क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस व भाजपा लड़ाई में नज़र आ रही है। गोवा में सत्ताधारी भाजपा की समस्याएँ एक जैसी नहीं हो सकतीं। प्रत्येक राज्य में मतदाता वहां के प्रमुख राजनीतिक दलों की हैसियत या कुव्वत को देखकर अपने मत का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अपना चुनाव घोषणापत्र तैयार करता है। जिस प्रकार भारत की संस्कृति विविधतापूर्ण है

उसी प्रकार इसकी राजनीति भी विविधतापूर्ण है यही वही है कि राज्यों में सरकार अलग अलग दलों की बनती रहती है परंतु पिछले तीन दशकों से इसमें परिवर्तन आया है देखने में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल मतदाताओं को लुभाने के लिए वादा करने की हदें इस तरह पार कर जाते हैं जिनका तारतम्य जाकर भारत की संघीय व्यवस्था से नहीं जुड़ता। इस संबंध में क्षेत्रीय भावनाओं को उग्र तक बनाने के मुद्रे भी आ

जाते हैं। साथ ही चुनावी वादा करते हैं। साथ ही चुनावी वादा करते हैं।

की कोशिश करते हैं। इसकी बजह यह भी है कि जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वह लोगों द्वारा दिये धन पर ही चलती है। इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है।

भारत ने स्वतंत्रता के बाद जो लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई उसमें प्रत्येक नागरिक को मिलाकर एक वोट का अधिकार सबसे बड़ा संवैधानिक किन्तु मूलभूत अधिकार है जिसका सौदा किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। यही सुनिश्चित करने के लिए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की और किसी भी सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखते हुए सीधे संविधान से शक्ति लेने के लिए प्राधिकृत किया। मगर एक वोट की ताक़त की इस हकीक़त को राजनीतिक दल अक्सर हाशिये पर फेंकने की कोशिश करते हैं। चुनाव मतदाता की ताक़त का प्रदर्शन ही होते हैं, इसी बजह से चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करता है। विधान सभा चुनावों में मतदाताओं को बड़े से बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने नागरिक होने की अहमियत को जताना चाहिए और सत्ता में अपनी भागीदारी तय करनी चाहिए।

लोकतंत्र में हर पांच साल बाद आम जनता सत्तारुद़ रहे दल से उसकी सरकार द्वारा किये गये काम का हिसाब मांगी है। इस मायने में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड या गोवा अथवा मणिपुर या पंजाब की समस्याएँ एक जैसी नहीं हो सकतीं। अब तो इससे भी आगे मुफ्त सौगात तक बांटने के बादे होने लगे हैं।

लोकतंत्र में यह प्रवृत्ति बहुत घातक होती है क्योंकि इससे मतदाता को एक उपभोक्ता बनाकर देखने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। लोकतंत्र में मतदाता याचक कभी नहीं होता बल्कि वह मालिक होता है। याचक की भूमिका में राजनीतिक दलों के नेता होते हैं अतः ख़ैरत बांटने की प्रवृत्ति प्रभावी बना कर राजनीतिज्ञ इस समीकरण को उलटने सही उपयोग कर पाएगा।

तुकी एर्दोगान के राष्ट्रवाद से उपजे संकट

यूरोप का आधुनिक देश तुर्की अपने शीर्ष नेता रेसेप तैयब एर्दोगान की इस्लामिक राष्ट्रवाद की नीतियों से आर्थिक जंजाल में फँस गया है। यूरोप का एकमात्र इस्लामिक देश होने के बाद भी लंबे समय तक धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद के ज़रिए सामाजिक और आर्थिक रूप से अग्रणी यह देश पिछले दो दशकों से सत्ता में बने रहने की एर्दोगान की सनक का शिकार बन गया है। एर्दोगान दशकों पुरानी धार्मिक नीतियों के समर्थक रहे हैं इससे उन्हें बहुसंख्यक मुसलमानों का भरोसा हासिल करके सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रख सकें। लेकिन इसका खामियाज़ा तुर्की के आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसका प्रभाव गिरती अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक पड़ रहा है।

यूरोप के इस ख़ुबसूरत देश को एर्दोगान की दो दशक की राजनीति ने बदल कर रख दिया है। इस्लामिक बहुल यह देश विविधता के चलते दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखता था। यहां रूसी, आर्मेनियाई, अल्बेनियाई, कुर्द, यहूदी, ईसाई सहित कई नस्लें

और जातीय समूह समानता और धर्मिक स्वतंत्रता के साथ बढ़िया जीवन जीते थे। इसी कारण इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की पहचान मिली हुई थी। लेकिन लगभग दो दशक पहले

तुर्की में एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। एर्दोगान ने देश को सत्ता में बने रहने के लिए इस्लाम को राष्ट्रवाद से जोड़कर इसे लोकलुभावन बनाने की कोशिश शुरू

की और यहां से इस देश में वैचारिक कट्टरता को बढ़ावा मिलने लगा।

सत्ता में आने के बाद एर्दोगान ने इस्लाम को सर्वोपरि मानने और दिखाने की राजनीतिक और सामाजिक कोशिशें

शुरू कर दी थीं। यह क्वायद इस विविधता वाले देश में अभूतपूर्व थी और साथ ही समाज को असहज करने वाली भी। पन्द्रहवीं सदी के इस्लामिक आटोमन साम्राज्य को आधार बना कर एर्दोगान देश में विभाजनकारी भावनाएं उभार रहे हैं। उनकी इन कुटिल कोशिशों के कारण तुर्की की बहुलतावादी पहचान को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। आधुनिक तुर्की के निर्माता माने जाने वाले कमाल पाशा ने तुर्की के निर्माता जाने वाले कमाल पाशा ने तुर्की को एक आधुनिक यूरोपीय देश के रूप में स्थापित करने के लिए मज़हबी अदालतें खत्म कर दी थीं, धार्मिक कट्टरपंथी ताक़तों को रोकने के लिए इस्लामिक ख़लीफाओं को खारिज कर दिया था। उनके उदार बदलावों से लंबे समय तक संचालित तुर्की ने एक मज़बूत राष्ट्र के रूप में जो पहचान बनाई थी। पर अब वही तुर्की गंभीर संकट में है। इसका प्रमुख कारण देश की सियासी राजनीति में एर्दोगान की धर्मिक नीतियां बन गई हैं, जो सत्ता

बाकी पेज 11 पर

यह दिल्ली है

यह दिल्ली है

यह दिल्ली है

पाकिस्तान में इमरान ख़ान हूकूमत को इस वर्ष मिल सकती है कड़ी चुनौती

2022 के दौरान पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और आर्थिक मंदी के तेज़ होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप शासन परिवर्तन या बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे, जो सुरक्षा और विदेश नीति विकल्पों के लिए गंभीर निहितार्थ वाले देश के लिए एक चुनौती होगी। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। 2018 से पाकिस्तान पर शासन करने वाला शासन 2021 में आंतरिक अंतरिरारोधों और बाहरी दबावों का बंधक बन गया।

रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक मोर्चे पर, इमरान ख़ान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पीटीआई सरकार एक संकट से दूसरे संकट में फँसती चली गई और बार-बार सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा बचाया गया। 2008 में संसदीय लोकतंत्र की वापसी के बाद से, कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, चाहे वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ के नवाज़ शरीफ। यह 2022 की शुरूआत है। बड़ा प्रश्न यह है कि इमरान ख़ान इस प्रवृत्ति के अपवाद कैसे और क्या होंगे? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि इस तरह की अस्थिरता से आर्थिक सुधार कैसे होगा? वर्ष 2022 में मौजूदा सेना प्रमुख क़मर अहमद बाजवा सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनके उत्तराधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाना है। 2021 में प्रधानमंत्री ने इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आई एसआई) के नए डीजी को सूचित करने के मुद्दे पर अपने पैर खींचकर अपनी पसंद स्पष्ट कर दी। अतीत के विपरीत नहीं, प्रधानमंत्री लंबे समय से खींचे गए संघर्ष में उलझे रहेंगे। यह वह प्रेरक शक्ति होगी जो या तो ख़ान को सत्ता से बाहर कर देगी या भविष्य के लिए उसे मजबूर करेगी।

वीकेंड कपर्फू में भी लगते रहे चौके-छक्के

राजधानी दिल्ली में दिनों जारी वीकेंड कपर्फू में दिल्ली के लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है, क्यों दिल्ली में कोरोना ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली थी। एक ही दिन में 20 हजार से ज़्यादा मामले सामने आने के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है इसलिए दो दिन का कपर्फू (लॉकडाउन) दिल्ली वालों को बोर कर रहा है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में डीडीएमए के आदेश पर दो दिनों के लिए वीकेंड कपर्फू लगाया जा रहा है। डीडीएमए के इस आदेश को पूरी सख्ती से पालन करवाना ज़िला प्रशासन की मुख्य ज़िम्मेदारी है।

लेकिन ज़िला प्रशासन डीडीएमए को निर्देशों को सख्ती से पालन कराने में असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। इस बानी देखने को मिला है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जैसे बदरपुर के ताजपुर, लाल किला के पिछे का ग्राउंड अन्य इलाकों के पार्कों में नौजवान डीडीएमए के आदेशों को ताक पर रखकर दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं और चौके छक्के लगाते रहते हैं। एक ओर यहां प्रशासन नदारद रहता है, वही दूसरी ओर यहां पर सुबह से लेकर शाम तक काफी संख्या में स्थानीय युवक क्रिकेट खेलते रहते हैं। विकेट गिरने पर एक दूसरे से गले

मिलना, जश्न मनाना, हाथ मिलाना,

आदि जो नियम कोरोना में मना है धड़ले से किए जा रहे हैं। वहीं जब भी कोई टीम जीतती तो सभी एक होकर फोटो भी खिंचवाते हैं दिनभर

यही खेल जारी रहता है।

कई इलाकों में क्रिकेट खेल रहे इन युवकों की संख्या इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागना चाहता। हैरानी

करने वाली बात यह है कि कड़ाके

की सर्दी में पूरे दिन क्रिकेट देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग एक ही जगह इकट्ठा होते हैं लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रशासन कोई उपाय

करने के बारे में सोच न ही इन जगहों पर कोई कर्मचारी इन जगहों पर मौजूद नहीं होता। ऐसे में सवाल यह है कि अगर क्रिकेट खेलते समय इन युवकों में अगर एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो वह कितनों को संक्रमित करेगा।

दूसरा सवाल अब आम लोगों पर घर से बाहर निकलने पर पर पाबंदी है तो इन युवकों को किसकी इजाज़त पर क्रिकेट खेलने की आज़ादी मिली है। गौर करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के वीकेंड कपर्फू लग रहे हैं, दोनों दिन यही माहौल बना रहता है, और डीडीएमए के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गत वर्ष कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी काफी कुछ ऐसे क्रिकेट मैच जारी थे, इन नौजवानों का यह भी कहना है कि जब आईपीएल और अन्य खेल खेले जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते, हम घर में पड़े-पड़े बोर हो गए हैं, मोबाइल और टीवी भी कब तक देखें। परंतु यह एक तरह का जोखिम अगर एक भी नौजवान संक्रमित हुआ तो वो जाने कितनों को लपेटे में ले गा। प्रशासन को इन पार्कों में खेल रहे इन नौजवानों को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय करना चाहिए।

पुलिसकर्मियों को अब हर 10 साल में मिलेगा प्रमोशन

दिल्ली पुलिस में अब हर 10 वर्ष में पुलिसकर्मियों को प्रमोशन मिलेगा। यही नहीं, अब कांस्टेबल से इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर एसीपी रैंक तक बेरोकटोक जा सकेगा। इसी संबंध में एचआर डीविजन की विशेष आयुक्त यहां नंदा की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई।

सूत्रों की मानें तो इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि दिल्ली पुलिस में सीनियर एसीपी नाम से भी एक पोस्ट बनाने पर विचार किया गया जबकि 30 वर्ष की नौकरी कर चुके सब इंस्पेक्टर को यह पद दिया जाएगा। आगामी फरवरी माह में इसकी घोषणा हो सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है दिल्ली पुलिस सीनियर एसीपी होंगे। इसे लेकर कई महीनों से विराषि पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा चली है इसी कड़ी में इस महत्वपूर्ण विषय पर एचआरडी डीविजन की विशेष आयुक्त सुंदरी नंदा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और डीसीपी तक की गई। इस फैसले को लेकर दिल्ली पुलिस अधिकारियों में काफी खुशी है क्योंकि जो लोग लंबे समय से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें अब समय पर पदोन्नति मिलेगी।

हालांकि बैठक के दौरान ये विचार किया गया था दिल्ली पुलिस में 10 साल पहले भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर को लेकर होने वाली देरी लेकर होने वाली देरी पर इंस्पेक्टर बनाया जाए। इसमें 2011 बैच

तक के सब इंस्पेक्टर कवर होंगे और उन्हें इंस्पेक्टर बना दिया जाए। इसी तरह 2001 में भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में एसीपी बने। वहीं 30 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके सभी सब इंस्पेक्टर सीनियर एसीपी होंगे। पुलिस सूत्रों का कहना है दिल्ली पुलिस में सीनियर एसीपी होने के बाद इंस्पेक्टर का पद होता है, जिसकी तर्ज पर अब दिल्ली पुलिस में सीनियर एसीपी बनाए जाएंगे। इस फैसले को लेकर दिल्ली पुलिस अधिकारियों में काफी खुशी है क्योंकि जो लोग लंबे समय से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें अब समय पर पदोन्नति मिलेगी।

लोकतंत्र की रक्षा समय की विशेष आवश्यकता है

15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों की सौ वर्षीय गुलामी से देश आज़ाद हुआ और सत्ता की बागडोर भारतीय नेताओं के हाथ में आई तो सबसे पहला प्रश्न जो सामने आया। वह यह था कि और उन तमाम मुसीबतें और कठिनाईयों सब बराबर के शरीके थे जो अंग्रेजी साम्राज्य के हाथों आज़ादी के मतवालों को बर्दाशत किए थे इसलिए सबको यही चाहत थी कि आने वाले दिनों में देश चलाने के लिए एक ऐसी सरकारी व्यवस्था जो जो सब के लिए हो और सब का हो और सब लोगों की राय से बने, यह विचार अमेरिका के पहले राष्ट्रपति इब्राहीम लिंकन की जनतंत्र पर आधारित सरकार की परिचय जनता के ज़रिए के लिए जनता की सरकार के मुताबिक था इसलिए यह फैसला किया गया कि भारत के लिए सबसे उचित सरकारी व्यवस्था “लोकतांत्रिक व्यवस्था” ही हो सकती है फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलाने के लिए पहले कानूनसाज असेम्बली बनाई गई और फिर एक संविधान बनाने वाली कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मशहूर कानून विशेषज्ञ बाबा साहेब आंबेडकर का चुनाव किया गया। देश का यह लोकतांत्रिक संविधान 26 जनवरी 1950 को बन कर तैयार हुआ और फिर उसी संविधान के लिए 1952 के पहले आम लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ।

सही बात यह है कि लोकतंत्र की सही कल्पना अल्पसंख्यकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार के बिना असंभव नहीं क्योंकि एक मिसाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक की हैसियत बढ़े भाई की तरह होती है और उस पर यह ज़िम्मेदारी आती है कि वह अल्पसंख्यकों में भरोसा और एहसास पैदा करे ताकि अल्पसंख्यक राष्ट्रहित और संयुक्त हित में बहुसंख्यक से मिलकर आगे बढ़ सकें, वरना तर्जुबा यह बताता है कि असंतुष्ट और कुचले हुए अल्पसंख्यक अक्सर लोकतंत्र के लिए बन जाती हैं जैसाकि आजकल श्रीलंका, फिलीपीन, आयरलैंड, सोमालिया और इजराइल में दिख रहा है, कि वहां के अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यक का जीना हराम कर दिया है इसलिए अगर यह कहा जाए तो ग़लत न होगा कि बहुसंख्यक सरकार की सफलता का राज़ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और खुशहाली में छुपी है कि जैसाकि महात्मा गांधी ने भी कहा, “लोकतंत्र का बुनियादी उसूल यह है कि कमज़ोर तरीन व्यक्ति को इंतेहाई शाहज़ोर के मुसाबी मवाका हासिल हों।”

लेकिन भारत में बहुसंख्यकों के कुछ भाग्य आज़माने बातों ने लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था समझ लिया है जिसमें बहुसंख्यक की मर्जी व मंशा के अनुकूल प्रशासन चलाई जाती हो हालांकि यह लोकतंत्र की ओछी और नामुकम्मल तारीफ़ है, जिसके साथ उसे सरकारी व्यवस्था तक सीमित कर देना और भी नादानी है क्योंकि लोकतंत्र केवल एक सरकार की कार्यशैली का नाम नहीं बल्कि वह एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें हर स्तर पर लोकतांत्रिक उसूल व आदाब पर अमल किया जाता हो और जब तक पूरा समाज ऐसा न होगा उस समय तक वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना दुश्वार होगा।

दुर्भाग्य से भारत में आज लोकतंत्र के नाम लेवाओं, दावेदारों और पूजने वालों की संख्या जितनी अधिक है लोकतंत्र पर सच्ची आस्था रखने वालों, उस के असली अर्थ को जानने वालों संख्या उतनी ही कम है और ऐसे लोग बराबर बढ़ते जा रहे हैं जो लोकतंत्र को बहुसंख्यक की तानाशाही समझते और दूसरों को समझते हैं, जबकि सच पूछा जाए तो भारत अल्पसंख्यकों का देश है जहां विभिन्न संस्कृतियों, रंगों, नस्लों और भाषाओं के लोग बड़ी संख्या में अपवाद है। जिन्हें देखा जाए तो बराबरी के अधिकार मिले हुए हैं लेकिन बारीकी से देखा जाए तो बहुसंख्यक को पहले दर्जे की नागरिकता और राष्ट्रीयता प्राप्त है जबकि अल्पसंख्यक बेआरामी का जीवन बसर कर रहे हैं और उनमें भी सबसे अधिक मसाएल और परेशानिया अगर कोई शिकार है तो वह मुसलमान और केबल मुसलमान है। जिनको पहले अंग्रेजों ने अपनी राजनैतिक हित को बज़ह से एक सौ साल तक अनदेखी की, अब आजाद भारत में भी वह राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 70 सालों से अपने अधिकार से वर्चित है छठी दशक में गृहमंत्रालय की ओर से सेंटर फॉर डेवलपमेंट सोसायटी के निर्देशक डॉ. गोपाल कृष्णा ने इस बारे में मुस्लिम समाज का सर्वे किया तो उसे प्रणाम का कम्प्यूटर के ज़रिए विश्लेषण करने पर यह चौका देने वाली बात सामने आई थी कि मुसलमानों के हर वर्ग और निचले वर्ग में उनका स्तर हर विभाग दूसरों के मुकाबले में सबसे नीचे हैं यानि जीवन स्वर के लिहाज़ से वह अछूतों से भी नीच पहुंच गए हैं। उनके यहां तालीम छोड़ने वालों की संख्या सबसे अधिक है इसी रोज़ग़ार की उपलब्धता या सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत आबादी के मुकाबले काफी नीचे हैं। इस सच्चाई के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने अच्छी तरह बयान कर दिया है।

यूपीए सरकार ने मुसलमानों के शिक्षा, आर्थिक और समाजी हाल जानने और उसकी भरपाई के लिए रिटायर जज राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने काफी मेहनत के बाद एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि इस समय मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक व शिक्षा स्तर दलितों से भी बदतर है उसने इस बारे में कुछ अनुशंसाएं भी की थीं और मनमोहन सरकार ने उनको मानते हुए कार्यवाई भी की, मगर उसी समय 2014 में सत्ता बदलकर भाजपा के हाथ में आ गया और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेन्द्र मोदी विराजमान हो गए इसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चर कमेटी के विश्लेषण क्या हश हुआ, मोदी जी महाराज के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने वही किया जिसकी उम्मीद थी इसलिए उसे मुसलमानों की तुष्टिकरण वाली रिपोर्ट बताकर ठांडे बस्ते में डाल दिया, आज किसी को यह भी ख़बर नहीं कि सोर्स कौन से खाई में धूल चाट रही हैं फिर भी हम आज लोकतंत्र, लोकतंत्र खेल रहे हैं मगर लोकतंत्र आज कहाँ और किस रूप में है, इस पर बहरहाल विश्लेषण की ज़रूरत है। हमारे ख्याल में आज भारत में लोकतंत्र अपनी खूबियों के विपरीत एक अजीब दौर राहे पर खड़ा है। एक और विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी सरकार है जो देश में लोकतंत्र

खुतबाते सीरिये तैयिबा

मुफ्ती मुहम्मद सलमान मंसूर पुरी किस्त-107

इसी दिन (पैर) को सकाफ़ा बनी साइदा में मशवरे में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अऱ्ह की खिलाफ़त का मामला तय हुआ, और अल्लाह तआला ने एक अहम फैसला यह फ़रमाया कि खिलाफ़त के सिलसिले में जो इख्लाफ़त होने लगे थे वे ख़त्म हो गए।

तज़हीज़ व तकफ़ीन और तदफ़ीन

अब यह मरहता आया कि दफ़ن कहाँ किए जायें? नमाज़ कैसे पढ़ी जाए? तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अऱ्ह ने फ़रमाया कि हुज़र ही ने फ़रमाया था कि नबी की जहाँ वफ़ात होती है, वहीं दफ़ن किया जाता है, चुनान्वे यह तय हो गया कि उसी हुजरे में तदफ़ीन होगी, फिर यह बाज़ गैबी इशारत की बुनियाद पर तय हुआ कि आप को बैरू कपड़े उतारे हुए ऊपर से गुस्त दिया जाये, चुनान्वे मंगल की सुबह को गुस्त की कार्बाई शुरू हुई, आप के करीबी अइ़ज़ा हज़रत अल्ली रज़ि अल्लाहु अऱ्ह, हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अऱ्ह और दीगर हज़रत गुस्त की सआदत में शारीक रहे। (अल रौज़ुल अनफ़ 4/442-451-452)

उसके बाद नमाज़ शुरू हुई, अंबिया अलैहिमस्सलाम की नमाज़ आम लोगों की तरह नहीं होती, बल्कि अकेले अकेले पढ़ी जाती है, पूरे मदीना वालों को नमाज़ पढ़नी थी इस लिए लाइन लगा कर लोग हुजरा-ए-मुबारक में जाते रहे और नमाज़ पढ़ते रहे, पहले मर्दों ने पढ़ी, फिर बच्चों ने पढ़ी और बाद में औरतों ने पढ़ी, पूरा मंगल का दिन और बुध की रात में तहज्जुद के बहुत तक नमाज़ पढ़ी जाती रही, फिर वहीं पर आप की तदफ़ीन हुई। (अल रौज़ुल अनफ़ 4/452) जब आप की तदफ़ीन हो गई, तो हज़रत फ़तिमा ज़हरा रज़ि अल्लाहु अऱ्ह ने हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु अऱ्ह से फ़रमाया कि: “तुम्हरे दिल ने यह बात कैसे गवारा कर ली कि तुम ने पैग़म्बर अलैहिमस्सलाम के जस्ते अकदस के ऊपर मिटी डाली?

फिर कब्र से मिट उठाई और फ़रमाया:

तर्जुमा: जो शख़्स नबी-ए-अकरम सल्ललल्लाहु अलैहिव व सल्लम की कब्र की मिटी सूंघ ले, उस के बाद ज़िंदगी भर कोई चीज़ सूंघने के काबिल न रहे तो बजा है। मेरे ऊपर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि अगर दिनों पर यह पहाड़ टूटता, तो वे दिन दिन न रहते, सब के सब रात बन कर रोशनी खो बैठते।

हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु अऱ्ह फ़रमाते हैं कि जिस दिन पैग़म्बर अलैहिमस्सलाम मदीना मुनब्वरा तशरीफ लाए तो मदीना के दर व दीवार चमकते हुए और रोशन महसूस होते थे, और जिस दिन आप ने वफ़ात पाई तो पूरे मदीने में एक तरह की जुलमत और तारीकी छाई हुई थी कि आज सरवरे दो आ़लम और ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्ललल्लाहु अलैहिव व सल्लम रूख़सत हो गए। (शमाइले तिर्मिज़ी 27)

लेकिन बहर हाल जाना तो हर एक को है, यहाँ न कोई हमेशा के लिए आया है और न हमेशा के लिए आयेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्ललल्लाहु अलैहिव व सल्लम से ज्यादा अल्लाह का मुकर्ब कौन होगा? जब आप ही न रहे और परदा फ़रमा गए, तो और कौन रह सकता है? लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अगरचे आप हमारी नज़रों से परदा फ़रमा चुके लेकिन अपनी कब्र-ए-अतहर में बाह्यत तशरीफ़ फ़रमा हैं और जो आप की खिलाफ़ में हाज़िर होता है आप खुद उसके सलाम को समाअत फ़रमाते हैं और जवाब मरहमत फ़रमाते हैं, कुछ रिवायात में है कि जिस ने मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया कि उस ने ज़िंदगी में मेरी कब्र की ज़ियारत की। (अल बहरूल अमीक़ 5/2887, अल-सुननुल कुबरा लिल बैहकी, 5/403)

अल्लाह तआला बार बार आप के रौज़ा-ए-अकदस पर हाज़िरी की तौफीक अता फ़रमाये, आमीन! □□

को फलने-फूलने का दावा कर रही है जिसका लाभ केवल एक समुदाय तक सीमित दिख रहा है और आखिर लोकतांत्रिक प्रशासन में एक चुनी हुई सरकार के कार्यशैली का जो स्तर है उस पर हमारी केन्द्र सरकार क्यों खरी नहीं उत्तर पा रही है, यह ऐसे प्रश्न है जिन्हें आज मोदी और उनके सत्ता के साझीदार सत्ता के नशों में अनदेखी कर सकते हैं मगर जब हिसाब का दिन आएगा तब वह क्या करेंगे, उन्हें सोचना चाहिए। बहरहाल हम अपनी गणतंत्र की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जिसके लिए हम अपने पढ़ने वालों को शुभकामना देते हुए उम्मीद करते हैं कि वह देश में लोकतंत्र की रक्षा और निरंतरता के लिए शान्तिपूर्ण और सत्यता से संघर्ष जारी रखेंगे। □□

नरेन्द्र मोदी ने कृषि कूनूनों के लिए माफ़ी मांगी क्या कांग्रेस ने 84 मुद्दे पर कभी खेद जताया?

मनोज तिवारी

प्रश्न:- किसान आंदोलन से भाजपा को जो डेंट लगा है कि आप क्या सोचते हैं पंजाब में भाजपा का उदय होगा?

उत्तर:- देखिए, निश्चित रूप से होगा। मैं एक गुरुद्वारे में एक ग्रन्थी की बात सुन रहा था, वह कह रहे थे कि नरेन्द्र मोदी तीन कृषि कूनून लाए, जब विरोध हुआ तो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी मांगी लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी 1984 के मुद्दे पर माफ़ी मांगी या खेद जताया? कभी नहीं। क्या यह एक बड़ी चज़ नहीं है, पंजाब को एक बार भाजपा को मौका देकर उसको देखना चाहिए। गृहीत किसी भी इंसान से हो सकती है, किसी व्यवस्था को समझने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्चे मन से सही हृदय से लोगों की सेवा करना चाहती है, इसलिए पंजाब में हम इन बातों को लेकर जाएंगे। अब तो कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की पार्टी से भी तालमेल की बात हो रही है। मुझे विश्वास है कि हम पंजाब में बड़ा रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं।

भाजपा सांसद एवं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान एक ख़ास मुलाकात में दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ की राजनीति पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने तीनों राज्यों को लेकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। पेश है मनोज तिवारी की इस बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्न:- पिछली बार चुनाव में कांग्रेस को 78 सीटें मिली थीं। इस बार भी नवजोत सिंह सिद्ध दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी?

उत्तर:- देखिए, नवजोत के बयान अगर ध्यान से सुनें तो वह अपनी सरकार को ही ठोकते रहते हैं लेकिन हैं इनसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। सिद्ध की जो अपनी चाल है, अपना संवाद है, स्टेटमैट्स हैं वे पंजाब के लोगों को याद हैं। हमें तो पंजाब को एक बेहतर पंजाब बनाना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पंजाब का विश्वास चाहती है।

प्रश्न:- इस बार कांग्रेस, आप और भाजपा के बीच मुक़ाबला होगा। क्या सोचते हैं?

उत्तर:- देखिए, आम आदमी पार्टी को जितनी चीटिंग करनी थी, वह दिल्ली में कर चुकी है। उनकी चीटिंग उजागर भी हो गई है। दिल्ली के

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब कहीं जाकर (चाहे पंजाब हो या चंडीगढ़) उस जगह को नशामुक्त करने की बात कहेंगे तो लोग पूछेंगे ही कि दिल्ली में क्या किया। जगह जगह गलियों में रेवेन्यू के लिए शराब की दुकानें खोल रहे हैं, दिल्ली त्रस्त है। दिल्ली में खड़े कूड़े के पहाड़ों से जनता परेशान है और केजरीवाल दूसरी जगह जाकर उसको कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कराने के वायदे कर रहे हैं ताकि यहां के लोगों को उनका वास्तविक हक़ मिल सके, जो भाजपा सरकार और शासन देते हैं। पंजाब में आम जनता का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सभा में टीचर्स और कच्चे मुलाजिमों को हक़ मांगने पर पीटा जा रहा है। हम पंजाब जाएंगे और वहां के लोगों को जागरूक करेंगे कि दूसरी पार्टी वायदे क्या करती है और असलियत में होता क्या है।

प्रश्न:- चंडीगढ़ निगम चुनाव की बात करें तो दिल्ली से कांग्रेस की स्वास्थ्य व्यवस्था हैं शिक्षा के नाम पर भी वह झूठ बोलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में 25वें स्थान पर आता है।
प्रश्न:- क्या आप पंजाब में भी डेरे लगाएंगे, क्योंकि यहां के कांग्रेस लीडर भी वहां प्रचार कर रहे हैं?
उत्तर:- हम निश्चित रूप से पंजाब जाएंगे। पंजाब को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से बचाकर रखना है ताकि यहां के लोगों को उनका वास्तविक हक़ मिल सके, जो भाजपा सरकार और शासन देते हैं। पंजाब में उस पर गर्व है, हम उसे ठीक कर रहे हैं और कई चीजें जैसे जिसकी दृग्गी थी, उनमें बहुतों को तो हमने मकान दे दिया और कुछ बचे हैं उन्हें भी जल्द देने के लिए प्लान बना चुके हैं। जल्द चंडीगढ़ टोटल स्लम प्री बना दिया जाएगा। हमने जितना काम चंडीगढ़ के लिए किया है उसके बारे में बहुत साथ है। कोई भी आए प्रचार के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता विकास को बोट करती है, जो हमने किया है। विकास के दम पर ही हमने चुनाव लड़ा है।

विधानसभा चुनाव-2022 संक्रान्ति से सियासी लहर

प्रश्न:- चरण के चुनाव में खास फैक्टर?

उत्तर:- पहले व दूसरे चरण में प० यूपी की 113 सीटों पर बोटिंग होगी। पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण हावी था, भाजपा 85 सीटें जीती थीं। लेकिन, इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। इन सीटों पर जाटों के अलावा दलित, मुस्लिम व यादवों का वर्चस्व है। तीसरे और चौथे चरण में 119 सीटें हैं। इनमें 31 सीटें एससी के लिए रिजिर्व हैं। इटावा और कन्नौज सपा के बढ़े रहे हैं जबकि, अवध में भाजपा मजबूत रही है। पांचवें चरण में 60 सीटें हैं। इनमें अमेठी-रायबरेली भी हैं, जो पहले कांग्रेस का गढ़ रही है। अयोध्या-प्रयागराज में भी इसी चरण में बोटिंग होगी, जो भाजपा की राजनीति के केन्द्र में है। छठे चरण में 57 सीटें हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर शामिल है आखिरी चरण में बनारस में बोटिंग होनी है।

प्रश्न:- ये चुनाव पिछली बार से अलग कैसे?

उत्तर:- चरण-धर्म के साथ इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर किसान प्रभावी हैं। यहां 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद यहां के बोटर भाजपा के साथ आएंगे या विपक्ष के, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, राम मदिर निर्माण शुरू होने के बाद भाजपा के लिए यह पहला बड़ा चुनाव है।

प्रश्न:- अयोध्या, काशी, मथुरा का क्या असर?

उत्तर:- आस्था के लिहाज़ से 80 प्रतिशत हिन्दू आबादी वाले यूपी में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कर्णिडोर और मथुरा की कृष्ण जन्मस्थली को भव्यता देने की बातें एक ख़ास वर्ग पर डालती हैं। कई

चुनौतियों जूझ रही भाजपा हिन्दुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है।

प्रश्न:- क्या दलित बोट बसपा के साथ रहेगा?

उत्तर:- पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बसपा की बोट हिस्सेदारी लगातार गिरी है। 2007 में 30.4 प्रतिशत बोट मिले थे। 2012 में 25.9 प्रतिशत व 2017 में 22.4 प्रतिशत 85 सीटों में से 69 भाजपा ने जीती थीं। बसपा इस बार सबसे कम सक्रिय है। भीम आर्मी का जनाधार भी सीमित हैं ऐसे में दलित बोटबैंक का कुछ हिस्सा भाजपा और सपा में जा सकता है।

प्रश्न:- इस बार गठबंधन का नया गणित?

उत्तर:- इस बार गठबंधन के साथी बदल गए हैं। भाजपा ने अपना

दल और निषाद पार्टी से हाथ मिलाया है। पिछली बार सुभासपा साथ थी,

लेकिन इस बार वह सपा के साथ चली गई। सपा ने कई छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। ये दल गैर प्रमुख पिछड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें राजभर, बिंद, पाल, प्रजापति, चौहान और अन्य हैं। सर्वे बताते हैं कि इनकी बदलाव भाजपा ने 2014 के बाद 50 प्रतिशत तक बोट हासिल किया है। सपा ध्रुवीकरण का काट इन्हें के सहारे पाना चाहती है।

प्रश्न:- मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या स्थिति है?

उत्तर:- 18-20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले यूपी में 143 सीटों पर इनका प्रभाव है। 70 सीटें ऐसी हैं,

जहां 20-30 प्रतिशत मुस्लिम बोटर हैं। 73 सीटों पर 30 प्रतिशत से ज़्यादा मुस्लिम हैं और 36 सीटों पर मुस्लिम अपने दम पर उम्मीदवार जितना सकते हैं।

प्रश्न:- महिला-युवाओं के लिए क्या खास?

उत्तर:- कांग्रेस का ऐलान है कि वह 40 प्रतिशत सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा ने महिला मतदाताओं को केन्द्र में रखकर 'कमल शक्ति संवाद' कार्यक्रम शुरू किया है। 20 लाख युवाओं तक पहुंचने के लिए भाजपा ने युवा संवाद शुरू किया है।

प्रश्न:- पार्टियों के चुनावी मुद्दे क्या हैं?

उत्तर:- सपा और कांग्रेस ने किसान और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है। प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी पर निशाना साथ रही हैं। भाजपा ने सपा और कांग्रेस को परिवारवाद की राजनीति करने वाली भ्रष्ट पार्टी कहकर पलटवार किया है। बसपा दलितों के मुद्दे उठा रही है।

लोकतंत्र में जनता की भलाई सबसे महत्वपूर्ण

दूसरी लहर के दौरान हुए चुनावों में कोरोना के कारण अनेक लोगों की जान चली गई रैलियों में लाखों लोगों का करीबी शारीरिक संपर्क होता है, जो कोविड सुपर स्प्रेडर्स हैं। राजनीतिक नैतिकता की मांग है कि हम अनुभव से सीखें और ग़लत विकल्पों को त्याग दें।

सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नैतिक श्रेष्ठता आम जनता की भलाई के प्रति सत्ता की जवाबदेही में निहित है। साथ ही लोकतांत्रिक वैधता चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर मानी जाती है जो लोगों को अपनी इच्छानुसार चुनाव की सुविधा प्रदान करती है। एक जीवंत लोकतंत्र की ये मूलभूत शर्तें महामारी के समय में कसौटी पर हैं। अकाट्य चिकित्सा साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि वायरस की संक्रमित करने की क्षमता पूरी तरह से वायरस या उसकी प्रचंडता पर निर्भर नहीं है, बल्कि वायरस और मानव समाज के बीच कैसे संपर्क होता है, इस पर भी निर्भर करती है। अनुभवजन्य अध्ययनों ने पुष्टि की है कि 8 प्रतिशत संक्रमित लोग कोविड के 60 से 80 प्रतिशत मामलों के लिए ज़िम्मेदार है।

और पिछले अनुभव ने बिना किसी संदेह के इस बात को साबित किया है कि चुनावी प्रक्रियाएं जिनमें भारी भीड़ की भागीदारी होती है और रैलियों में लाखों लोगों का करीबी शारीरिक संपर्क होता है, कोविड सुपर स्प्रेडर्स है। दूसरी लहर के दौरान हालिया चुनावों के भयावह परिणाम हमारे सामने हैं, जिसमें कोरोना के कारण अनेक लोगों की जान चली गई।

वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि वायरस की संक्रमित करने की क्षमता पूरी तरह से वायरस या उसकी प्रचंडता पर निर्भर नहीं है, बल्कि वायरस और मानव समाज के बीच कैसे संपर्क होता है, इस पर भी निर्भर करती है। अनुभवजन्य अध्ययनों ने पुष्टि की है कि 8 प्रतिशत संक्रमित लोग कोविड के 60 से 80 प्रतिशत मामलों के लिए ज़िम्मेदार है। आने वाले 4 से 8 सप्ताहों में अत्याधिक संक्रामक ओमिक्रॉन के चरम पर पहुंचने की आशंका है, जिससे बीमारी

का प्रसार तेज़ होगा।

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्तमान आरओ वैल्यू 1/22 है, जो कि महामारी के प्रसार की तेज़ी को दर्शाती है। देश के कई जिलों ने पहले ही 10 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी रेट की जानकारी दी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगाह किया है कि तीसरी कोरोना लहर में, हमें पिछले पीक की तुलना में 3-4 गुना बढ़ि देखने को मिल सकती है। निकट भविष्य में ये एक भयावह राष्ट्रीय चिकित्सा आपातकाल के स्पष्ट संकेत है। समयबद्ध चुनावों की आवश्यकता राजनीतिक लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, जिसका नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षित करने की उच्च संवैधानिक अनिवार्यता के साथ स्पष्ट रूप

से विरोध दिख रहा है।

यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि व्यावहारिक वास्तविकता यह है कि चुनावों के दौरान आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल के प्रभावी अमल के माध्यम से वायरस के प्रसार को रोकना लगभग असंभव है। कड़े विकल्प कभी आसान नहीं होते लेकिन अक्सर आवश्यक होते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि चुनावों का टालने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को झटका लग सकता है, जिससे सत्तारुद्धरण करकरे अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सत्ता का आनंद ले सकती है, जो रास्ता अलोकप्रिय सरकारें विशेषाधिकार के रूप में अपनाती हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कोविड के कारण जुलाई 2020 तक 31 देशों में विभिन्न

स्तरों पर चुनाव अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए थे।

भारत के मामले में, यह तर्क दिया जाता है कि चुनावों को स्थगित करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से परे है और ऐसा केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें व्यापक राजनीतिक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होती है जो मौजूद नहीं है लेकिन अत्यावश्यक राष्ट्रीय चिकित्सा आपातकाल के आधार पर राज्य विधानसभा के लिए संविधान में संशोधन करना संभव होना चाहिए। राजनीतिक नैतिकता की मांग है कि हम अनुभव से सीखें और ग़लत विकल्पों को त्याग दें। कोविड के चलते कुछ राज्यों में रात और सप्ताहांत के कर्फ्यू सहित अन्य स्थानीय प्रतिबंध

मौजूदा स्थिति में विधानसभा चुनावों के आयोजन के कारण स्पष्ट रूप से असंगत है। एक ओर लॉकडाउन और चुनावी गतिविधियों की अनुमति की अतार्किकता लोगों की बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाती है और हमारे नेताओं की मंशा पर प्रश्न उठाती है। लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को ख़तरे का सामना करते हुए, हम वास्तव में यह नहीं कह सकते हैं कि गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति के कारण कुछ सप्ताहों या महीनों के चुनाव स्थगित करने का मतलब लोगों की भलाई के लिए एक भारी कीमत चुकाना है या कि यह हमारे लोकतंत्र को गंभीर रूप से ख़तरे में डाल देगा। इसके विपरीत, त्रिपुरा चुनावी आयोजन एक विश्वसनीय लोकतंत्र के रूप में

कोविड के चलते कुछ राज्यों में रात और सप्ताहांत के कर्फ्यू सहित अन्य स्थानीय प्रतिबंध मौजूदा स्थिति में विधानसभा चुनावों के आयोजन के कारण स्पष्ट रूप से असंगत है। एक ओर लॉकडाउन और दूसरी ओर चुनावी गतिविधियों की अनुमति की अतार्किकता लोगों की बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाती है और हमारे नेताओं की मंशा पर प्रश्न उठाती है।

हमारी साख पर प्रश्न खड़ा करेगा। मतदाता अपेक्षा रखते हैं और वास्तव में यह उनका अधिकार है कि वे महामारी के भय से मुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मौजूदा परिस्थितियों में यह अकल्पनीय है कि सरकार/चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यक गारंटी दी जा सकती है।

इनमें विचार-विमर्श के पूर्ण और प्रभावी अवसर, भागीदारी की समानता, चुनाव प्रबंधन की गुणवत्ता, प्रतियोगिता की समानता और आवश्यक चिकित्सा प्रोटोकॉल सहित नियमों को लागू करने के लिए एक आवश्यक वातावरण उपलब्ध कराना भी शामिल है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती साधन और साध्य के बीच सही संतुलन तलाशना है। केन्द्र सरकार को देश को यह बताना चाहिए कि वह प्रमुख संवैधानिक मूल्य-जीवन के अधिकार पर ज़ोर देने से क्यों हिचकिचाती है।

रोज़गार

लेखपाल बनने का है सुनहरा मौक़ा, 8085 पदों पर आजमा सकेंगे किस्मत

लगभग दो वर्ष से जब से कोरोना काल आया है यूँ तक ज़िन्दगी के हर क्षेत्र पर असर पड़ा है, हमारी ज़िन्दगी में रहन सहन, खान-पान और अन्य सभी चीज़ों में बदलाव आया है। कोरोना ने सबसे ज़्यादा असर नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा है, एक अनुमान के अनुसार कोरोना के कारण सिर्फ भारत में एक करोड़ के आसपास लोगों की नौकरी गई, और इतने ही लोगों की सैलरी आपी, या उससे भी कम कर दी गई। कंपनियों ने छंटनी की नीति अपनाई, वे भी बेबस थे कोरोना के कारण माल, सप्लाई, उपभोग सब चीज़ बुरी तरह प्रभावित हुई। यूँ सरकार दावे करते रहती है कि उसने रोज़गार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं इन्हीं में एक अवसर उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के पदों पर करीब सात वर्ष बात भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में प्रतियोगी अभ्यर्थी के पास राज्य में लेखपाल बनने का सबसे सुनहरा अवसर है। इसलिए पात्र युवाओं को बिना समय गंवाएं तुरंत तैयारी में लग जाना चाहिए और एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए अनेक संस्थान सहायक कोर्स करा रहे हैं इनमें स्पेशल लेखपाल फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइंन कर तैयारी कर सकते हैं।

किन विषयों की करनी होगी तैयारी

उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, गणित व ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एग्जाम कुल 100 अंकों का होता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में ग़लत उत्तर देने वाले कैंडिडेट्स के एक चौथाई अंक भी काटे जाएंगे। ऐसे में लेखपाल भर्ती के मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों

को तुरंत कांप्सेप्ट पर आधारित तैयारी की शुरूआत कर देनी चाहिए।

कितना मिलेगा वेतन

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, विभाग के अंतर्गत अंतिम रूप से लेखपाल के पदों पर चयनित होने वाले युवाओं को ग्रेड पे-2000 व वेतन बैंड-5200 से 20,200 रूपये हिसाब प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता जैसी राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने वाली अन्य सुविधाओं का भी पूरा लाभ मिलता है। पुष्टेन्द्र सिंह - 'यूपीएसएससी की पीईटी का आवेदन तो कर दिया था लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते कोर्चिंग न मिल पाने को लेकर काफी परेशान था। तभी मैंने ऑनलाइन बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर बिना समय गंवाएं बैच को ज्वाइंन कर लिया जहां अन्य फैकल्टी ने इस एग्जाम को क्रेक करने में मेरी मदद की और मैंने इस परीक्षा में 99.85 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसी तरह अनेक छात्रों को अपने तैयारी पूरी करने के लिए अनेक तरह के ऑनलाइन कोर्सेज को करके फायदा होता है और एग्जाम उनके लिए इसी हो जाता है।

□□

येरुशलम : इजराईली पुलिस ने येरुशलम के पड़ोस में स्थित एक विवादित संपत्ति फलस्तीनी नागरिकों के कब्जे से खाली करा लिया और इमारत को ढहा दिया। यह कार्रवाई काफी समय से चल रही तनातनी के बाद की गई। शेख ज़र्ज़ के आवासीय इमारतों में रह रहे फलस्तीनी नागरिकों की शुरुआत में इलाकाखाली कराने आए पुलिसकर्मियों से हिंसक झड़पे हुई थीं पास के इलाके में स्थित कई अन्य संपत्तियां भी विवादों के घेरे में हैं।

तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा

चीन ने अफग़ानिस्तान में तालिबान के अंतरिम शासन से कहा है कि उसे वैश्विक मान्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। तालिबान ने वैश्विक समुदाय की मान्यता पाने के लिए चीन से सहायता करने की अपील की थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाओ लीजियान ने मीडिया से कहा 'हम उम्मीद करते हैं कि अफग़ानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों पर खतरने, मुक्त और समावेशी राजनीतिक माहौल बनाने, नरम और विवेकपूर्ण घरेलू तथा विदेश नीति अपनाने सभी दिशा में क़दम बढ़ाएगा।

पाकिस्तान ने भवनों के अंदर जमावड़े पर लगाई रोक

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर वाले इलाकों में भवनों के अंदर जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है। देश में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते हुए यह यह क़दम उठाया गया है। लगातार दो दिन 5000 से अधिक मामले सामने आने संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के तहत यह क़दम यह सख्त क़दम उठाया गया है।

तुर्की में विस्फोट के बाद तेल की प्रमुख पाइपलाइन बंद

अंकारा : दक्षिण पूर्वी तुर्की में विस्फोट के बाद एक प्रमुख पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है, जिससे इराक से विश्व बाजारों में तेल भेजा जाता था। रिपोर्ट के अनुसार कहरमान मरअस प्रांत के पाजारजेक शहर के पास हुए विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिससे अधिकारियों को एक राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा। विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ। पाइपलाइन से उत्तरी इराक के किरकुक तेल क्षेत्रों से तुर्की के जेजान बदरगाह तक तेल पहुंचाया जाता है।

अजीजन बाई-उस्मानी पाज़ेब से निकलती थी क्रांति की हुक्मार

सन् 1857 में देश में पराधीनता के विरुद्ध जो क्रांति हुई उसमें देश के बेटों और बेटियों ने एक सा बलिदान दिया, शत्रुओं से लौहा लिया और अपने रक्त से स्वतंत्र यज्ञ में आहुति दी। अपने अधिकार और अपने देश की स्वतंत्रता की मांग करने वालों ने इस संग्राम को स्वाधीनता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई अथवा क्रांति नाम दिया, तो ब्रिटिश शासकों ने इसे गदर, विद्रोह तथा राजद्रोह आदि नाम देकर इस आवाज़ को दबाने तथा कुचलने का प्रयास किया। इस रक्तरंजित क्रांति की विशेषता यह रही कि सन् 1857 में वे तलवारें भी म्यानों से बाहर आ गई जो कई सालों से निष्क्रिय थीं और इसी कारण शत्रु देश में पांच पंसारता गया। भारत की बेटियों ने आज़ादी के इस संग्राम में हिस्सा ही नहीं लिया, अपितु नेतृत्व भी किया। आज़ादी की आग जब देशवासियों के दिल को जलाने लगी तब कानपुर की एक नर्तकी बीरांगना बन गई जिसका नाम है अजीजन बाई। अजीजन बाई ने संभवतः अपने जीवन में कभी दुर्गा मां की पूजा न की होगी, पर उस भारतीय बेटी के हृदय, आत्मा में मां दुर्गा का अंश निश्चित ही था। वह उस शक्ति से ओतप्रेत थी, जिसे दुर्गा शक्ति कहा जाता है। इस युद्ध की जिस क्रियाशीलता और साहस का परिचय दिया उससे यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व तथा पहचान के लिए माता-पिता, कुल गोत्र आदि के नाम की आवश्यकता नहीं रहती, उसका कर्म ही परिचय बन जाता है।

अजीजन बाई कानपुर की नर्तकी मात्र ही थी, जो नृत्य के साथ लोगों का मनोरंजन करती थी और आलसी तथा विलासी जीवन बिता रही थी। अचानक ही उसके जीवन में तब परिवर्तन आया जब स्वतंत्रता संग्राम अर्थात् क्रांति की चिंगारी मेरठ और दिल्ली से भड़कती हुई कानपुर पहुंची तथा क्रांति की लड़ाई का मुख्य केन्द्र कानपुर ही बन गया। 1857 के जून माह में कानपुर के किले पर नाना साहब और अंग्रेजों में घमासान हुआ। इस युद्ध की विशेषता यह रही कि देशप्रेम का परिचय देते हुए महिलाओं ने भी सैनिकों की सहायता कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी संग्राम में अजीजन बाई के कार्य ने उसे एक तंग अधेरी गली से निकालकर इतिहास का अंग बना दिया।

इस प्रथम युद्ध में अंग्रेजों को जोरदार टक्कर देते हुए क्रांतिकारियों ने विजय प्राप्त की और नाना साहब को बिठुर का स्वतंत्र शासक घोषित

कर दिया, पर यह खुशी अधिक दिन न टिकी, 16 अगस्त 1857 को ही बिठुर में अंग्रेजों के साथ फिर युद्ध हुआ जिसमें क्रांतिकारी परास्त हो गए। इन दोनों ही युद्धों में अजीजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उसके दाम काम बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक तो क्रांति नायक तात्या टोपे की आज़ानुसार अपनी नर्तक मंडली सहित अंग्रेज छावनियों में जाकर नृत्य एवं संगीत द्वारा उनका मनोरंजन करना और गुप्त रूप से उनकी योजनाओं का सारा समाचार ले आना। यह बहुत हिम्मत और ख़तरे का काम था, पर अजीजन बाई न पीछे हटी, न कभी घबराई। उसने अपने काम में सहयोग देने के लिए मस्तानी महिला मंडली का गठन किया। इन महिलाओं को उसने स्वयं ही प्रशिक्षित किया तथा युद्ध कार्य से लेकर घायल सैनिकों की सेवा करने तक का काम उन्हें सिखाया। अजीजन में एक सफल सेनानायक और संगठनकर्ता के सभी गुण थे। एक इतिहास लेखक के अनुसार वह बगल में हथियार लटकाए, हाथ में नंगी तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर उसे बिजली की तरह तेजी से दौड़ाती हुई शहर की गलियों और छावनी के बीच चक्कर लगाती रहती थीं। घायल सिपाहियों को औषधि, दूध, भोजन आदि पहुंचायती और इसी की ओट में सैनिकों को हथियार भी उपलब्ध करवा देती।

बिठुर और कानपुर के दोनों ही युद्ध में अजीजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। देशभक्तों के लिए वह जितनी कोमल, और मृदु हो जाती,

युद्ध विमुख होकर भोगने वालों से उतनी ही वीरता और कठोरता से पेश आती। वीरों को वह प्रेम का पुरस्कार देती, पर कायरों को धिक्कारती। महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने अजीजन की तारीफ करते हुए लिखा है - अजीजन एक नर्तकी थी, परंतु सिपाहियों को उससे बेहद स्नेह था। उसका प्यार साधारण बाजार में धन के लिए नहीं बिकता था, उसके प्यार का पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता जो देश से प्रेम करता था। अजीजन ने यह सिद्ध कर दिया कि वह वास्तव में ही वीरांगना है। यद्यपि वह एक पेशेवर नर्तकी थी, पर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए उसने घुंघरू उतार दिए और रसिकों की महफिल सजाने वाली अजीजन क्रांतिकारियों के साथ बैठकें करने लगी।

इतिहासकारों के अनुसार बिठुर में

हुए युद्ध में पराजित होने के बाद नानासाहब और तात्या टोपे को कानपुर छोड़ना पड़ा, लेकिन अजीजन पकड़ी गई। युद्धबद्दिनी के रूप में उसे जनरल हैबलॉक के सामने पेश किया। उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर अंग्रेजी अधिकारी मुग्ध हो उठे। पिछले लंबे समय से वे उसकी सुंदरता, नृत्य कला और वीरता के समाचार सुन रहे थे, पर अजीजन ऐसी अनुपम सुंदरी होगी कि सोचा भी न था। जनरल हैबलॉक ने उसके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यदि अजीजन अपनी गलतियों के लिए अंग्रेज शासन से क्षमा मांगेगी तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वह अपनी नृत्य महफिलों फिर से सजा सकेगी अन्यथा कड़ी से कड़ी सजा

लक्ष्मीकांत चावला

भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अजीजन ने न केवल क्षमा मांगने से इंकार कर दिया, अपितु उसने शेरनी की तरह गरजते हुए यह भी कह दिया कि माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भारतवासियों पर इतने जुल्म किए हैं। वह कभी भी अंग्रेजों को इन अमानवीय अत्याचारों के लिए माफ़ नहीं करेगी। अजीजन जानती थी कि यह सब कहने का परिणाम मौत है, फिर भी भी भारत की यह बेटी अंग्रेजों के सामने गरजती रही। एक नर्तकी से ऐसा जबाब सुनकर अंग्रेज अफसर लाल पीले हो गए, उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया गया और देखते ही देखते सैनिकों ने उसका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता की दीवानी अजीजन ने अंग्रेज अफसरों का आदेश सुनते ही गर्व से सिर ऊंचा किया और मुस्कुराती हुई स्वयं ही फायरिंग स्क्वायर्ड के सामने जाकर खड़ी हो गई।

भारत की बहुत ही बहादुर बेटी थी अजीजन। वह देश के लिए शहीद हो गई। स्वातंत्र्य समर में अपना जीवन दे गई, पर उसे अपने देशवासियों से यही शिकायत ज़रूर होगी कि स्वतंत्रता भारत में अजीजन को वह नाम और स्थान नहीं मला जिसके वह योग्य थी। आज की आवश्यकता यह है कि स्वतंत्र भारत की बेटियों को अजीजन से परिचित करवाएं, जिससे वे भी राष्ट्रहित कर्मपंथ पर निष्ठा और वीरता के साथ चल सकें।

मिस जैनेट रेनकिन-जो युद्ध के विरुद्ध पहली आवाज बनी

वह इस दुनिया में अपनी तरह

की पहली आवाज़ थी। अमेरिका में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वह सबसे आगे और सबसे व्यवस्थित थीं, तभी उन्हें उनके क्षेत्र मॉटाना के लोगों ने चुनकर कांग्रेस में भेजा था। वैसे महिलाओं की स्थिति आज भी अमेरिकी राजनीति में बहुत अच्छी नहीं है और इन नई महिला सांसद का महत्व इस बात से पता चल सकता है कि उनके बाद आज तक कोई महिला उनके क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसी विरल महिला का महत्व जितना अधिक होता है उस पर जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक होती है। लोग कान और ध्यान लगाए रहते हैं, कि ऐसी महिला क्या बोलेगी,

उसकी मंशा क्या है?

बहरहाल, उन दिनों मतलब आज से 104 वर्ष पहले दुनिया में जितना तनाव था, उससे कहीं ज़्यादा तनाव में अमेरिकी कांग्रेस थी। सबसे बड़ा प्रश्न था कि अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में उतरना चाहिए या नहीं? आज भी जब अमेरिका कहीं हमले के लिए तैयार होता तो वहां जैनेट रेनकिन की याद ज़रूर आती है कि वह खड़ी होंगी और युद्ध के खिलाफ़ वोट करेंगी। वह 7 नवंबर, 1916 को पहली बार कांग्रेस के लिए चुनी गई थीं। वह आज भी प्रेरित करती हैं कि धारा के विपरीत खड़ी होना, असहमत होना कितना मायने रखता है।

अमेरिकियों को विज्ञान और व्यवसाय का शौक था, वहां संस्कृति ऐसी ही थी कि व्यवसाय को सबसे बेहतर काम समझते थे। इसलिए युद्ध में उतरना अमेरिकियों को अच्छा

सुधीर
विद्यार्थी

शहीद-ए-वृतना के मज़ार पर फूलों की कैफियत

काकोरी के शहीद अशफाक उल्लाह खां के खत्रू और डायरी के पत्रे हमारे सामने बिखरे पड़े हैं। शाहजहापुर शहर में रेलवे स्टेशन के नज़दीक पुराने एमनर्जई मुहल्ले का उनका घर इस क्रांतिकारी की विरासत है, जहां उनके पौत्र के साथ बैठकर अशफाक की लिखावट को पढ़ने समझने की हमारी कोशिशें बहुत सफल नहीं हो पा रही हैं। नौ अगस्त 1928 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के निकट रेल रोककर सरकारी खजाने को हथियाने के मुक़दमे में उत्तर भारत के जिन चार प्रमुख क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिया गया, उनमें अशफाक भी थे। 19 दिसंबर, 1927 को फैज़ाबाद जेल में फांसी पर जाने से पहले उन्होंने डायरे के पन्नों पर जो कुछ दर्ज किया, वह हिन्दुस्तान की मुक़म्मल आज़ादी का नक्शा है। उनकी हस्तलिपि में कुछ गज़लें हैं, जिनमें ‘हसरत तख़ल्लुस है। मरने से पहले अपनी आखिरी ख़वाहिश को इन ज़बातों के साथ उन्होंने दर्ज किया था,

कुछ आरज़ू नहीं है, है आरज़ू तो यह है,

रख दे कोई ज़रा सी ख़ाके - ए-
वर्तन में कफ़न में।

अब हम अशफाक के घर के नज़दीक उस खानदानी कब्रिस्तान में हैं, जहां फांसी के बाद फैज़ाबाद से लाकर वह दफ़त किए गए थे। कैसा रहा होगा वह नज़ारा, जब उनका मृत देह का सामना उनकी माँग को करना पड़ा। अशफाक की शहादत के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके भाई रियासतउल्ला ख़ा से कहा था, ‘तुम इनकी कच्ची कब्र बरवा दे, हम पुख्ता करा देंगे और इनका मकबरा ऐसी बनवाएंगे, जिसकी नज़ीर यूपी में न होगी।’ गणेश शंकर जी खुद 25 मार्च, 1931 को शहीद हो गए, तब शहर कांग्रेस कमेटी ने अशफाक की आखरी आरामगाह को पक्का कराकर उस पर छत डलवा दी। फिर चहारदीवारी बनी, बगीचा लगा और अब वह एक मकबरे की शक्ल में है। मैं इस वक्त अशफाक की कब्र के सिरहाने खड़े होकर प्रशासनिक और सरकारी तामज्जाम से दबे इस क्रांतिकारी की रुह की बेचैनी को महसूस कर रहा हूं, जहां उनकी विचार यात्रा और लक्ष्यों को

पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। ‘साझा शहादत, साझा विरासत’ के इस सबसे बड़े स्मारक पर कुछ सूख चुके फूल अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं। सालों पहले इस मुहल्ले का नाम ‘अशफाक नगर’ किया जा चुका है, जहां से आधे कोस दूर पर ‘बिस्मिल’ का मुहल्ला है। अशफाक और बिस्मिल मिशन हाई स्कूल में पढ़े वहां उनकी यादों के बिखरे फूलों को चुनने की मोहल्लत किसी के पास नहीं है और न ही यह जानने की हसरत कि 1918 में ‘मैनपुरी षड्यंत्र केस’ में इस विद्यालय के छात्र राजाराम भारतीय की यहां हुई गिरफ्तारी ने ही अशफाक को क्रांतिकारी बनने की ओर प्रेरित किया था। इस शहर में सबसे पहले स्वतंत्रता के रजत जयंती वर्ष (1972) में बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह की प्रतिमाएं बयालीस के सेनानी वासुदेव गुप्त के प्रयत्नों से स्थापित की गई। बीस वर्ष पहले जब अशफाक के घर का पुराना दालान नई तामीर के लिए तोड़ा गया, तब किसी के ज़ेहन में यह नहीं गूंजा कि इस घर की मिट्टी में चन्द्रशेखर आज़ाद

की आमद के भी निशान हैं। काकोरी मुक़दमे के दौरान आज़ाद कुछ रक़म देने चुपके से उनके भाई के पास आए थे। फैज़ाबाद जेल से लिखी अशफाक की चिट्ठियां एक पुराने बक्से के चोरी चले जाने से नष्ट हो गई। फिर भी वह कुरआन शरीफ बचा रहा, जिसे गले में लटकाकर वह फांसीघर की ओर बढ़े थे। उसके शुरुआती पत्रे पर अशफाक की हस्तलिपि है। फैज़ाबाद के फांसीघर से लिखे अशफाक के वे ख़त भी हम देख रहे हैं, जो उन्होंने अपने मुक़दमे के साथी शचीदनाथ बख्ती की बहन प्रमिला और वकील कृपाशंकर हजेला को लिखे थे। ये इबारतें उनके सघन क्रांतिकारी रिश्ते का सबसे बड़ा साक्ष्य है। अशफाक की शहादत के बाद 19 दिसंबर, 1969 को पं. बनारसीदास चतुर्वेदी के संपादन में उर्दू में यादगारे अशफाक किंताब छपी, जिसके उनके भाई अपने जीवनकाल में देख सके। फैज़ाबाद जेल के फांसीघर के परिसर में लगी अशफाक की प्रतिमा पर प्रतिवर्ष जलसा होता है। वहां वह तख्ता अभी सुरक्षित है, जिस पर खड़े होकर उन्होंने फांसी के फंदे को गले में डाला और शहीदों की टोली में जा मिले। प्रदेश की चंद्रभानु गुप्त सरकार की वह घोषणा पूरी नहीं हुई कि रोशनउदौला कचहरी प्रांगण में शहीद अशफाक का स्मारक बनाया जाएगा, जहां बख्ती जी के साथ उन पर काकोरी का पूरक मुक़दमा चला, और न ही लखनऊ का ‘रिंग थियेटर’ हम बचा पाए, जिसके किराये पर लेकर ब्रिटिश सरकार ने काकोरी के मुख्य मुक़दमे की कार्यवाही को अंजाम दिया था। फैज़ाबाद में अब फैज़ाबाद बचा ही कितना है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि यह शहर अपने सीने में अशफाक का यह शेर बहुत संभाल कर रखेगा,

तांग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से,

चल दिए सूए अदम जिन्दाने फैज़ाबाद से।

अशफाक की कब्रगाह से शहर की ओर चलते हुए हमें फांसी के एक दिन पहले अपने बकील हजेला साहब से कहे गए उनके शब्द बेसाखा याद आ रहे हैं, ‘एक गुज़ारिश है आपसे कि कल आकर देखिए कि आखिर मैं किस शान से फांसी पर चढ़ता हूं’ हजेला जी ने उत्तर कि ‘वह नज़ारा देखने की जुर्म मुझ में नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी कब्र पर ज़रूर आऊंगा।’ अशफाक की इस अंतिम शरणस्थली पर आकर हजेला जी को हर बार बहुत सुकून मिलता था, गोया उन्होंने अशफाक से जी भर कर बातें कर ली हों।

एक गुमनाम शहीद पीर अली ख़ां

वर्ष 1820 में आज़मगढ़ के मुहम्मदपुर गांव में जन्मे पीर अली किशोरावस्था में ही घर से भागकर पटना चले गए थे। वहां एक नवाब मीर अब्दुल्लाह ने उनकी परवरिश की। मीर साहब की मदद से पीर अली ने पटना में किताबों की एक दुकान खोल ली। कुछ लोग पीर अली ख़ां को जिल्दसाज भी बताते हैं। कामकाज के सिलसिले में वह कुछ क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी वह दुकान धीरे धीरे क्रांतिकारियों के अड़े में तबदील हो गई। उनकी दुकान पर क्रांतिकारी साहित्य मंगाए जाते, फिर वहां से बेचे जाते थे। देश की आज़ादी पीर अली के जीवन का उद्देश्य बन गई थी। उसी दौरान दिल्ली के क्रांतिकारी अज़मुल्ला ख़ान से उनका संपर्क बना और आसपास के इलाकों में घूम घूमकर उन्होंने क्रांतिकारी मिजाज़ के युवाओं को संगठित और प्रशिक्षित करना शुरू किया।

1857 की क्रांति का बिहार में भी भारी असर हुआ। गया, छपरा, पटना, मुज़फ्फरपुर और मोतिहारी जैसी जगहों में क्रांतिकारियों ने अनेक अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। क्रांतिकारियों का मुक़ाबला करने के लिए अंग्रेज़ों ने दानापुर में एक छावनी स्थापित की। लेकिन दानापुर के सैनिक मेरठ की घटनाओं के कारण

अंग्रेज़ों का दमन चक्र चला और अनेक निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ के घर तोड़े गए, तो कुछ को झूठी मुठभेड़ बताकर गोलियां से भून डाला दिया। आखिर पांच जुलाई, 1857 को पीर अली और कुछ सैनिक भी शहीद हुए। जबकि पीर अली अपने कुछ साथियों के साथ बच निकलने में सफल हुए।

अंग्रेज़ों का दमन चक्र चला और अनेक निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ के घर तोड़े गए, तो कुछ को झूठी मुठभेड़ बताकर गोलियां से भून डाला दिया। आखिर पांच जुलाई, 1857 को पीर अली और कुछ सैनिक भी शहीद हुए। जबकि पीर अली अपने कुछ साथियों के साथ बच निकलने में सफल हुए।

अंग्रेज़ों का दमन चक्र चला और

खास खबरें

नर्सिंग होम में आग लगने से छह की मौत

मैद्रिड : स्पेन के एक नर्सिंग होम में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वैलेंसिया के क्षेत्रीय प्रमुख शिमो पुइग ने कहा कि 20 के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनमें कई हालत गंभीर हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने वैलेंसिया उत्तर में मोंकाडा नगर पालिका के नर्सिंग होम से निकाले गए कुल 70 मरीजों में से 25 लोगों को बचाया।

यूक्रेन को 20 करोड़ डॉलर की सहायता देगा अमेरिका

कीव : अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन ने यूक्रेन दौरे के बीच बाइडेन प्रशासन को कहा कि वह रूसी आक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र यूक्रेन को 20 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन की रक्षा के संबंध में अमेरिकी प्रयासों के तहत सहायता को मंज़ूरी दी गई।

ट्रम्प के कई सहयोगियों को भेजा समन

वाशिंगटन : अमेरिका में कैपिटल हिल (संसद भवन) हिंसा मामले की जांच कर रही प्रतिनिधि सभा की समिति ने हाल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के करीबी रूडी गिलियानी सहित उनके कुछ सलाहकारों को समन जारी किया। समिति लगातार ट्रम्प पर शिकंजा करने की तैयारी कर रही है। इस बार समिति ने गिलियानी, जेना एलिस, सिडनी पॉवेल और बोरिस एपशेटिन को पूछताछ और गवाही देने के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है।

अफगान संकट से बड़े पैमाने पर जा रही नौकरियां

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क में पांच लाख से अधिक लोगों से उनकी नौकरी छिन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महिलाओं और सरकारी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के अलावा कृषि, सामाजिक सेवा व भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। बड़ी संख्या में लोगों को या तो रोज़गार गंवाना पड़ा है या फिर उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई कंपनियां अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रही हैं, और उनके लिए वह कर्मचारियों की छटनी भी करने को मजबूर हैं।

शराब और नशीले पदार्थों की विनाशकारिया ①

मौलाना मु॰ सलमान मंसूरपुरी

इस दौर में जो गुनाह अधिक और तेज़ी से फैल रहे हैं उनमें शराब शराबनोशी और नशो की वस्तुएं हैं। इस्लाम दीने फिरत है और बेशक इस्लामी तालीमात ही इंसानियत की बक़ा की अकेली ज़मानत है। इसीलिए इस्लाम में शराब को “उम्मुल खबाइस” यानि सारी बुराईयों की जड़ बताया गया है और यह ऐसी हक़ीक़त है जिस को साबित करने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर समझ रखने वाला इंसान की इंसानियत का मदार उसकी अक़ल और समझदारी पर है, यही अक़ल, इंसान को दूसरे जानवरों से अलग करती है। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नशो का इस्तेमाल करने से इंसानी अक़ल ठप्प हो जाती है और आदमी अच्छे और बुरे के बीच तमीज़ करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है, यहां तक कि पानी और पेशाब में भी फर्क नहीं कर सकता, इसी तरह बीबी और बहन में भी फर्क नहीं कर पाता, इसलिए कितने ही नशेबाज़ सड़क के किनारे फुटपाथों पर ज़्लील जानवरों की तरह पड़े नज़र आते हैं। इंसानियत की इस तजलील को इस्लाम कभी बर्दाश्ट नहीं कर सकता इसीलिए अलग अलग अवसरों पर उसके नुकसानात बताने के बाद अल्लाह ने कुरआन पाक में शराब और नशा की हुमर्त पर अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए फरमाया

“ऐ ईमानवालो! यह शराब, जुआं और बुत, सट्टा के तीर यह सब शैतान के गंदे काम हैं, तुम उनसे बचते रहो, ताकि निजात पाओ, शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे बीच शराब और जुएं के ज़रिए दुश्मनी और हसद डाल दे और तुम को अल्लाह की याद से और नमाज़ से रोक दे, सो अब तुम बाज़ आ जाओ। (अलमाइता 90-91)

इसलिए इस हुक्म के आने के बाद मदीने में सहाबा कराम ने शराब के मटके फोड़ डाले और मशकीज़ों के मुंह खोल दिए जिसकी बजह से मदीने की गली कूचों और नालियों में शराब बह पड़ी।

शराब और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते

इस्लाम की नज़र में शराब का पीना और नशा करना ईमान के सख़ा ख़िलाफ़ है, यहां तक कि नशा की हालत में नशाबाज़ व्यक्ति ईमान की रोशनी से वंचित कर दिया जाता है, इसलिए नबी-ए-पाक सल्लू. ने इरशाद फरमाया -

“ज़िना करने वाला ज़िना करते समय मोमिन नहीं रहता, चोरी करने

बाला चोरी करते समय ईमान से महरूम रहता है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत उसमान ग़नी रज़ि० से एक लम्बी हदीस मंकूल है जिस में उन्होंने एक वाकेआ बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, “क़सम खुदा की! कहीं भी ईमान और शराब की आदत जब भी जमा होते हैं तो उनमें से एक दूसरे को जल्द ही निकाल बाहर करता है।

शराब लानत का सबब है

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लू. को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि “मेरे पास जिब्रील अलैहि० तशरीफ़ लाए और यह फरमाया ‘ऐ मुहम्मद! बेशक अल्लाह तआला ने शराब पर, उसके बनाने वाले पर, उसको बनाने वाले पर और उसके पीने वाले और उसे उठाने वाले और जिसके पास उठाकर ले जाया गया हो और उसके बेचने वाले पर और उसके खरीदने वाले पर और उसके पिलाने वाले और पीने वाले पर लानत और फटकार फरमाई। (खाहो अहमद)

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है, ‘रसूल अकरम सल्लू. ने शराब की बजह से दस आदमियों पर लानत भेजी है (1) शराब निचौड़ने वाले पर (2) उसको निचौड़ने वाले पर, (3) उसको पिलाने वाले पर, (4) शराब उठाने वाले पर, (5) जिस के पास शराब ले जाई जाए, (6) उसको पिलाने वाले पर, (7) उसको बेचने वाले पर, (8) उसकी कीमत खाने वाले पर, (9) उस को खरीदने वाले पर, (10) जिसके लिए खरीदी गई हो उस पर। (तिर्मिज़ी, इन्नेमाज़ा)

जिस दस्तरख्बान पर शराब पिलाई जा रही हो वहां बैठना हaram है

इस्लाम की नज़र में शराब कितनी काबिले नफ़रत चीज़ है, उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नबी-ए-करीम सल्लू. ने ऐसे दस्तरख्बान पर भी बैठने से मना फरमाया है, जहां शराब का दौर चल रहा है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ि० इरशाद फरमाते हैं, “ऐ लोगों! मैंने नबीए अकरम सल्लू. को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख़्म अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उस पर लाज़िम है कि वह ऐसे दस्तरख्बान पर न बैठे जहां शराब का दौर चल रहा हो। (मुसनद अहमद)

शराब को हलाल समझने वालों को बंदर और खिंज़ीर बना दिया जाएगा

बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ि० से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लू. ने इरशाद फरमाया :-“यक़ीन मेरी उम्मतों में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िना, रेशमी कपड़े, शराब और गाने बाजे को हलाल समझेंगे और कुछ लोग एक ऊचे पहाड़ के दामन में पड़ाव करेंगे, जहां चरवाहे उनके जानवरों को चराएंगे, एक फक़ीर शख़्म अपनी ज़रूरत के लिए उनके पास मांगने के लिए आएगा, तो वह यह कह देंगे कि आज नहीं कल आना। (यानि बिलावजह उसे टाल देंगे) तो अल्लाह तआला पहाड़ उन पर गिरा देंगे और दूसरे लोगों को क़ायमत तक के लिए बंदर और खिंज़ीर बना देंगे। (बुख़ारी शरीफ़) (जारी)

हम्दे बारी तआला

-हफीज़ ताइब

तू ख़ालिक़ हर आलम का या हय या क़य्यूम

हर पल तेरा रंग नया या हय या क़य्यूम

तू ज़ाहिर भी बातिन भी या बारी या फ़त्ताह

सब में बस कर सबसे जुदा या हय या क़य्यूम

तू है नूर अर्ज़ों समा या क़ादिर या कुदूस

नूर से अपने राह दिखा या हय या क़य्यूम

नूर तेरा है ताक़ के अंदर जलता एक चिराग़

या एक तारा मोती सा या हय या क़य्यूम

तू मन्नान है तू मन्नान है तू रहमानों रहीम

अहसन तेरे सब अस्मा या हय या क़य्यूम

पैदा करके इंसां को दी कुरआन की तालीम

बग़़शों तू ने नुत्कों नवा या हय या क़य्यूम

तू ने फलक को रिफ़अत दी और क़ायम की मीज़ान

हुक्मे तवाजुन सबको दिया या हय या क़य्यूम

तू ने ज़मीन का फर्श बिछाकर उसको किया सरसब्ज़

तू है कफ़ीले नश्वों नुमा या हय या क़य्यूम

वस्फ़ कहां तक लिखे तेरे ताइब हेचमदान

क्या वो और क्या उसकी सना या हय या क़य्यूम



(सूरा अल नस्र नं० 110)

अनुवाद और व्याख्या : शैखुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मदीने में उतरी इसमें तीन आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

जब अल्लाह की सहायता और फैसला आ पहुंचे।

बड़ी निर्णायक वस्तु यह थी कि मक्का विजयी हो जाये, इसी पर अरब के अधिकतर कबीलों की नज़रें लगी थीं। उससे पहले एक-एक दो-दो व्यक्ति इस्लाम में आते थे। मक्का विजयी हो जाने के पश्चात् टोलियों पर टोलियां दाखिल होने लगी। यहां तक कि पूरा अरब द्वीप इस्लाम का कलमा पढ़ने लगा और जो उद्देश्य रसूल भेजने का था पूरा हो गया।

और आप लोगों को अल्लाह के दीन में समूह-समूह प्रवेश होते देख लें तो अपने पालनहार की पाकी और प्रशंसा कीजिये।

अर्थात् समझ लीजिए कि आपको रसूल बनाकर भेजने और दुनिया में रहने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब आखिरत की यात्रा समीप है इसलिए इधर से निवृत्त होकर तन, मन से उधर ही लग जाइये और पहले से भी अधिक उपासना में तल्लीन हो जाइये और इन सफलताओं और विजय पर अल्लाह को धन्यवाद दीजिए।

रुकू नं।

और उससे गुनाह बरखावाइये निःसदेह वह बड़ा माफ करने वाला है।

अर्थात् अपने लिए और उम्मत के लिये क्षमायाचना कीजिए।

चेतावनी :-अल्लाह के रसूल का अपने लिए गुनाहों से माफी मांगना पहले अनेक स्थानों पर उसका वर्णन हो चुका है वहीं देख लिया जाये। हज़रत शाह अबुल कादिर साहब लिखते हैं अर्थात् कुरआन में हर जगह फैसले का वादा है और इनकारी फैसले में जल्दी करते थे। हज़रत की आखिरी उम्र में मक्का फतह कर लिया गया। अरब के कबीले दल के दल मुसलमान होने लगे। वादा सच्चा हुआ। अब उम्मत के गुनाह बरखावाया कीजिए ताकि शफाअत (सिफारिश) का दर्जा भी मिले। यह सूरत आखिरी उम्र में उतरी। हज़रत ने जान लिया कि मेरा काम जो दुनिया में था कर चुका। अब सफर है आखिरत का।

(सूरा अल्लहब नं० 111)

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें पांच आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूँ अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

अबुलहब के हाथ टूट गये और वह आप बरबाद हो गया।

अबुलहब (जिसका नाम अबुल उज्जा बिन अबुल मुतलिब है) हूँ मुहम्मद सल्लू. का हकीकी चाचा था, लेकिन ईर्ष्या और दुर्भाग्य के कारण हज़रत का कठोर दुश्मन था। जब आप किसी समूह में अल्लाह का कोई संदेश सुनाते तो यह दुष्ट पत्थर फेंकता। यहां तक कि आपके पांव लहू-लुहान हो जाते और मुंह से कहता - लोगों इसकी बात मत सुनो। यह अधर्मी और झूठा है। कभी कहता है हज़रत मुहम्मद सल्लू. हम से उन बातों का वादा करते हैं जो मरने के पश्चात् मिलेंगी। हमको तो वह चीज़ें नज़र नहीं आतीं। इसके पश्चात् दोनों हाथों को सम्बोधित करके कहता - तुम दोनों टूट जाओ कि मैं तुम्हारे अंदर उनमें से कोई चीज़ नहीं देखता जो मुहम्मद बयान करते हैं। एक बार हुजूर सल्लू. ने सफा पर्वत पर चढ़कर सबको पुकारा। आपकी आवाज

पश्चिमी यूपी में भाजपा के सामने गढ़ बचाने और विपक्षी के पास वजूद की रहेगी चुनौती

उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा के लिए दस फरवरी को मतदान होगा। पश्चिमी यूपी में भाजपा का 2017 का प्रदर्शन देखें तो यहाँ से इन्हें 54 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार चुनाव में चुनौतियां अलग हैं। तो इनके सामने गढ़ बचाने की चुनौती रहेगी। वहाँ विपक्षी दलों को किसान आंदोलन से मिली संजीवनी से क्या उनका वजूद बच पाएगा। यह तो परिणाम आने पर पता चलेगा।

2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में मेरठ विधानसभा में 7 में 6 भाजपा के खाते में गयी थीं। जबकि एक सीट भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराने वाले सपा के रफीक अहमद के खाते में गयी थी। मुजफ्फर नगर में सभी सीटें भाजपा के खाते में गयी थीं। शामली की तीनों सीटों में से दो पर भाजपा और एक पर सपा को विजयी मिली थी। बागृपत की तीन में से दो सीटों पर भाजपा और एक पर रालोद ने जीत दर्ज की थी हालांकि बाद में छपरौली विधायक ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी। गाजियाबाद की पांचों सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। हापुड़ की तीन विधानसभा सीटों में दो पर भाजपा और एक पर बसपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। गौतमबुद्ध नगर की तीनों और बुलंदशहर की सातों सीट भाजपा के खाते में चली गई थीं। आगरा में

सभी नौ और मथुरा की पांच में से चार सीटें भाजपा की जबकि एक सीट पर बसपा ने विजय पायी थी। 2017 के चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। रालोद और बसपा अकेले ही चुनाव मैदान में थे। लेकिन इस बार चुनाव में चुनौती रहेगी। वहाँ विपक्षी दलों को

रालोद और सपा एक साथ हैं। बसपा और कांग्रेस अकेले दम पर लड़ रहे हैं। इस बार पश्चिम के इन जिलों में किसान आंदोलन का असर होने की वजह से मुकाबले कड़े हो गए हैं। मेरठ के लोगों का यहाँ पर कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों के पशुओं की चोरी थमी है।

लोगों की बहन बेटियों को लोग परेशान करते थे, वह भी कम हुआ है। एकतरफा कार्रवाई नहीं है। इसलिए यह सरकार वापस होगी। वहाँ के रहने वाले जुबैर का कहना है कि इस सरकार ने आपस में लड़वाने का काम किया है।

किसानों को बहुत परेशानी से

गुजरना पड़ा है। बहुत परेशानी के बाद इन लोगों ने आंदोलन वापस लिया है। इसका असर तो चुनाव में दिखेगा। मुजफ्फर नगर के रहने वाले गिरीश कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में पहले कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, उससे कुछ सुकून मिला है। □□

उ० प्र०: आचार सहिता पालन से चूक तो कार्रवाई तय

उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों के चुनावों के आदर्श आचार सहिता लागू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पांचों राज्यों को नोटिस जारी कर आचार सहिता का सख्ती से पालर करने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने कहा, उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आयोग के मुताबिक आचार सहिता के दौरान सरकार के मंत्री व विधायक अपनी अधिकारिक यात्राओं पर चुनावी काम नहीं कर सकेंगे। उद्घाटन/शिलान्यास पर रोक रहेगी। पद का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार में नहीं करेंगे। सरकारी परिवहन जैसे विमान, वाहन, मशीनरी व कर्मियों का इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी के हित में करना सहिता का उल्लंघन माना

जाएगा। प्रचार व चुनावी बैठकों के लिए मैदानों, सार्वजनिक स्थलों व हेलिपैड का इस्तेमाल खुद के खर्च पर करना होगा। सरकारी खर्च पर विज्ञापन देना प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया से सरकारी पैसों से पार्टी का प्रचार करते पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की राजनीतिक खबरों या सरकार के कामों का प्रचार भी प्रतिबंधित होगा। आचार सहिता के दौरान मंत्री और अन्य अधिकारी सरकारी खजाने से किसी तरह भी का अनुदान या भुगतान नहीं कर सकेंगे। मंत्री किसी तरह की सरकारी मदद का वादा नहीं कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के किसी भी गेस्ट हाउस में

राजनीतिक दल कोई मीटिंग नहीं करेंगे। निर्वाचन के समय सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता ऐसा होने पर कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

आर्थिक या किसी और तरीके से मतदाताओं को प्रलोभन नहीं दिया जा सकेगा। दूसरी पार्टीयों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यपित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी। धार्मिक, स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, बैनरों के लिए नहीं किया जाएगा।

आचार सहिता लागू होते ही सरकार चुनाव डियूटी पर तैनात किये

गए अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं कर सकेंगी। अगर कुछ अफसरों के तबादले के आदेश आचार सहिता लागू होने से पहले आ गए थे लेकिन तबादले हुए नहीं इसके लिए सरकार को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। आचार सहिता के दौरान सिर्फ जेड या उससे ऊपर की श्रेणी वाले राजनीतिक पदाधिकारियों को ही सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगलों या अन्य सरकारी ठिकानों में ठहराने की अनुमति होगी। इसमें भी अगर चुनाव डियूटी का कोई अधिकारी ठहरा हो तो उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सरकारी ठिकानों पर प्रवास के दौरान ये लोग पार्टी प्रचार की गतिविधियों नहीं कर सकते। □□

मणिपुर और गोवा में क्या साख बचा पाएँगी भाजपा

आगामी विधानसभा चुनाव में मणिपुर, गोवा, यूपी और उत्तराखण्ड में सरकार को बचाकर फिर से जनादेश हासिल करना व साख बचाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। वहाँ पश्चिम बंगाल और दिल्ली में खेल बिगड़ चुकी टीएमसी व आम आदमी पार्टी, भाजपा की जीत में कांटे बिछा सकती है। मणिपुर में इस बार दो चरणों में (27 फरवरी व 3 मार्च) को तथा गोवा में (14 फरवरी) को चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मणिपुर व गोवा में उल्लेखनीय जीत हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन दोनों ही राज्यों में तेजी से सक्रियता दिखाते हुए भाजपा

ने कांग्रेस को मात देकर अन्य दलों का समर्थन हासिल कर सरकार का गठन किया था। इस बार भाजपा इन दोनों ही राज्यों में अपने बल पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाना चाहती है। दरअसल, 2017 के विधानसभा चुनाव में मणिपुर में भाजपा को राज्य की कुल 60 विधानसभा सीटों में से केवल 21 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस (35 प्रतिशत मत) के खाते में भाजपा से ज्यादा 28 सीट आई थी। हालांकि भाजपा का वोटिंग प्रतिशत करीब 36.1 फीसदी था। 2017 के चुनावों में मणिपुर राज्य एक ऐसे राजनीतिक करिश्मे से गुज़रा है, जब विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर पाई थी। फेरबदल

और दलबदल वाले इस राज्य ने सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचते कई मुख्यमन्त्रियों को देखा है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2022 के चुनावों में भी उलटफेर देखने को मिल सकता है हालांकि मणिपुर में सरकार बनाने के लिए सत्तारूढ़ दल भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है लेकिन टीएमसी की आहट ने मामले को थोड़ा रोक बना दिया है। मणिपुर में टीएमसी ने 2012 में सात सीटों पर जीत हासिल की थी और 2017 में भी एक सीट उसके कब्जे में आई थी। इसके अलावा पिछले दिनों नगालैंड में सुरक्षाबलों ने 14 आम नागरिकों को मारा दिया था, जिसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में सेना के खिलाफ़ नाराज़गी फैली और अफस्पा कानून (एएफएसपीए)

को वापस लेने की मांग हो रही है। इस बड़े मुद्रे के असर से मणिपुर भी अछूता नहीं बचा है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए भी अफस्पा (एएफएसपीए) कानून भी चिंता का विषय बना हुआ है, यह कानून सेना को विशेष ताकत देता है।

मणिपुर की तरह ही 2017 में गोवा में भी भाजपा ने कांग्रेस की अपेक्षा कम सीटें हासिल की थीं, लेकिन सरकार बनाने के जादुई आंकड़े को अन्य दलों के सहयोग से भाजपा ने हासिल कर लिया था और उसके बूते भाजपा ने उस समय प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। 2017 के चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा 32.48 प्रतिशत वोट तो हासिल हुए थे लेकिन सीटों के मामले में वह कांग्रेस से पिछड़ गई थी, इस

बार गोवा में आम आदमी पार्टी का कहना है कि वे कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़कर सरकार बनाएंगे। 'आप' ने मुख्यरूप से कांग्रेस को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अब देखना होगा कि क्या गोवा में 'आप' के दावे को धराशायी करते हुए भाजपा अपनी शाख बचाने में सफल हो पाती है या फिर 10 मार्च को तगड़ा झटका लगता है। 2017 में मणिपुर में कांग्रेस और भाजपा के बीच मतों का अंतर एक प्रतिशत से भी कम था, लेकिन अन्य दलों के सहयोग से मणिपुर में भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई थी। भाजपा का दावा है कि इस बार राज्य में अपनी सरकार के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के बल पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। □□

चोट और सर्जरी के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था ग्रैंड स्लैम में वापसी करना : यूकी

टेनिस ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज़ हो चुका है। इसमें भारत के 29 साल के यूकी भांबरी भी अपने एकशन में है। यूकी ने 2018 में आखिरी बार ग्रैंड स्लैम खेला था। चोट की वजह से उनका कैरियर प्रभावित रहा है। वे एक बार फिर चोट से उबरने के बाद कोर्ट पर हैं। उनका कहना है कि चोट या सर्जरी के बाद वापसी करना आसान नहीं होता है। पेश है आस्ट्रेलियन ओपन के से पहले यूकी भांबरी से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल:- आस्ट्रेलियन ओपन में आप वापसी कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी कैसी रही?

जवाब:- मैं हमेशा से ही इसमें खेलने के बारे में सोचता हूं। मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं और मैंने 2-3 महीने के लिए काफी तैयारी की है। यहां पर आना और खेलना मेरे लिए बड़ा गोल रहा है। मुझे कुछ एटीपी इवेंट खेलने का मौका मिला। ट्रेनिंग अलग बात होती है और मैच खेलना अलग बात होती है। मुझे मैन ड्रॉ में जगह बनानी है।

सवाल:- आपकी सर्जरी हुई, उसके बाद वापसी करना कितना मुश्किल रहा..?

जवाब:- मैं गेम का मज़ा लेता हूं और इस गेम से प्यार करता हूं। एक एथलीट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होता। इंजरी और सर्जरी का टाइम किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मेरा गोल यही थी कि ग्रैंड स्लैम में कमबैक करूं, मैं लकी हूं कि मैं यहां हूं, और आस्ट्रेलियन ओपन में

भाग लिया।

सवाल:- टूर्नामेंट का बायो बबल कितना चुनौतीपूर्ण है, नियम

कितने सख्त हैं?

जवाब:- कोरोना की वजह से हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह

से आयोजक काफी सतर्क हैं। ये

समय चैलेंजिंग हैं लेकिन जब आप टूर्नामेंट के लिए आते हैं तो ये सब

बातें आपके दिमाग में पहले से होती हैं। ये मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन गेम के लिए ये सब ज़रूरी भी हैं।

सवाल:- चोट लगने के बाद आपने गेम में किस तरह का बदलाव किए?

जवाब:- मैंने स्ट्रेंथ पर ज़्यादा समय बिताया है, मैं अपने घुटने की स्ट्रेंचिंग करता हूं और साथ में अपने एंकल और टांगों की भी। आराम करने पर भी पूरा ध्यान दे रहा हूं। मैंने ज़्यादा अपनी गेम में बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन चोट से बचने के लिए कुछ खास ज़रूर किया है।

सवाल:- जोकोविच को खेलने की अनुमति मिली जबकि भारत के अमन दहिया को नहीं मिली, इस पर क्या कहेंगे?

जवाब:- मुझे, इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे भी मीडिया से ही इस बारे में जानकारी मिली है। उन्हें क्यों परमिशन दी गई और क्यों नहीं रोका गया, इस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सरकार ही कुछ कह

मयंक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामांकित

भारत के सलामी बल्लेबाज़ मयंक अग्रवाल को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के कारण दिसंबर माह के लिए आइसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' (महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) पुरस्कार के लिए नामित किया गया। मयंक के अलावा, न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल और आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क को भी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मयंक मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ़ दूसरे टेस्ट में भारतीय जीत के सूत्रधार बने। उन्होंने दो पारियों में 150

और 62 बनाए जिससे भारतीय टीम ने मैच अपने नाम किया।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ सेंचुरियन में राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 117 रन की अहम साझेदारी कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस दौरान बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किल परिस्थितियों में 60 रन की शानदार पारी खेली। भारत में जन्मे न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने मुंबई टेस्ट में पारी के सभी 10 विकेट झटक कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। भारत के खिलाफ़ श्रृंखला के

दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने यह कारनामा किया। वह जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज़ बने।

बाएं हाथ के इस गेंदबाज़ ने इस दौरान सिर्फ एक टैस्ट मैच खेला जिसमें उन्होंने 16.07 की औसत से 14 विकेट लिए। स्टार्क ने भी इस दौरान बल्ले और गेंद दोनों के साथ असाधारण प्रदर्शन से आस्ट्रेलिया ने दो मैच बाकी रहते एशेज श्रृंखला अपने नाम कर ली और बाद में क्लीन स्वीप से हराया।

स्वास्थ्य

हेपेटाइटिस बी बेहद ख़तरनाक बीमारी

हेपेटाइटिस बी बेहद ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी है।

हेपेटाइटिस बी क्या है?

यह एक संक्रामक बीमारी है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) के कारण होती है। यह बीमारी लीवर को संक्रमित करती है। यह बीमारी धीरे-धीरे खतरनाक रूप ले लेती है। इससे सिरोसिस (लीवर की संरचना में क्षति, जिससे उसके क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं), लीवर का काम नहीं करना, लिवर कैंसर आदि हो जाते हैं।

यद्यपि 90 प्रतिशत संक्रमित युवा इस संक्रमण से निजात पा लेते हैं, लेकिन 10 प्रतिशत लोगों की समस्या बढ़कर पुरानी हेपेटाइटिस बी

(सीएचबी) बन जाती है। वास्तव में दुनियाभर में होने वाले लीवर कैंसर में से 60 प्रतिशत हेपेटाइटिस बी के कारण होते हैं।

हेपेटाइटिस बी के कारण

0.00 यह बीमारी संक्रमण से फैलती है। किसी व्यक्ति को यह बीमारी संक्रमित रक्त चढ़ाने, बिना सही तरह से स्टरलाइज्ड सूई के ज़रिए इंजेक्शन देने, टैटूइंग, रेजर, सर्जरी, नसों में डाली जाने वाली दवा या पानी आदि चढ़ाने से हो सकती है।

0.00 बच्चों में हेपेटाइटिस बी संक्रमण मां से हो सकता है। डिलीवरी के पहले महीने के भीतर कुछ महिलाओं में हेपेटाइटिस बी की आशंका बढ़ जाती है।

0.00 हेपेटाइटिस बी यैन क्रिया के द्वारा भी फैल सकता है।

.00 पुराने हेपेटाइटिस से संक्रमित होने की संभावना महिलाओं में दोगुना रहती है।

सीएचबी के लक्षण

एक व्यक्ति जो लीवर के संक्रमण का शिकार होता है, वह 45 दिन से लेकर 160 दिन के अंदर बुखार, जी मिचलाना, भूख की कमी, उल्टी पीलिया आदि का शिकार हो सकता है। यह खतरनाक स्थिति एक से लेकर तीन माह तक हो सकती है। उसके बाद या तो यह व्यक्ति ठीक हो जाता है या फिर सीएचबी का शिकार हो जाता है। एचबीवी से संक्रमित सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों में ही इस तरह के लक्षण दिखते हैं। बाकी लोग या तो इस बीमारी से ऊबर जाते हैं या फिर किसी लक्षण के बगैर वे गंभीर स्थिति के शिकार

हो जाते हैं। सीएचबी इस तरह एक साइटेंट किलर है।

एचबी ठीक होता है या नहीं

सीएचबी से पीड़ित काफी कम लोग ही इससे पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं। सीएचबी का इलाज लीवर के भीतर वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है ताकि सीएचबी की खतरनाक स्थिति न हो जाए। साधारण रक्त परीक्षण के ज़रिए इसका पता लगाया जा सकता है।

जन्म लेने वाले बच्चे को कैसे बचाएँ

● अगर आप वायरस से ग्रस्त हैं तो इलाज के लिए डाक्टर से परामर्श करें। ● जन्म के तुरंत बाद बच्चे के हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन ज़रूर लगावाएं। इसके बाद 12 घंटों के अंदर वेक्सीन की पहली खुराक दिलवाना न भूलें। ● अपने डाक्टर को बुलाएं अगर आपको हेपेटाइटिस बी के लक्षण होते हैं या आपको विश्वास है कि आपका संक्रमण किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसे हेपेटाइटिस है। अगर आप किसी यात्रा में जाने के सोच रहे हैं तो अपने डाक्टर से पूछें कि आपकी हेपेटाइटिस के टीके के सफर पर जाते बक्त ज़रूरत है या नहीं। □□

नोएडा : अस्पतालों में कोविड उपचार की दरें तय

प्रदेश शासन की ओर से निजी कोविड चिकित्सालयों में उपचार में निजी चिकित्सालयों के मनमानी शुल्क वसूली को रोकने के लिए शासर स्तर से यह कदम उठाया गया है। शहर और चिकित्सालय की श्रेणी के मुताबिक उपचार की दर निर्धारित की गई है। प्रशासन की ओर से निजी कोविड चिकित्सालयों के लिए जांच शुल्क निर्धारण वाला शासनादेश भेजा गया है। जनपद गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद 'ए' श्रेणी के शहरों में रखा गया है। जनपद में संचालित निजी कोविड चिकित्सालय 'ए' श्रेणी के लिए निर्धारित रेट के हिसाब से ही उपचार का शुल्क वसूलेंगे और यदि कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित चिकित्सालय के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। शासनादेश की प्रति जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजी गई है।

शासनादेश के मुताबिक 'ए' श्रेणी के शहरों में 'नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर हास्पिटल' से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय कोविड मरीज़ों को सपोर्टिंग केर, ऑक्सीजन और

सहयोगी सुविधा के साथ एकांतवास बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए एक दिन के अधिकतम 10 हजार रुपए ही वसूल पाएंगे। इसके साथ ही शासन ने गंभीर मरीज़ों के लिए आइसीयू बिस्तर के लिए अधिकतर 15 हजार रुपए प्रतिदिन और वैंटिलेटर सुविधा के साथ आइसीयू बिस्तर के लिए अधिकतम 18 हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित किए हैं। शासन ने एचएबीएच से गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के लिए भी शुल्क तय किए हैं। 'ए' श्रेणी वाले शहरों में ऐसे चिकित्सालय ऑक्सीजन और सहयोगी सुविधा के साथ एकांतवास बिस्तर के लिए अधिकतम आठ हजार रुपए, आइसीयू बिस्तर के लिए 13 हजार रुपए, और वैंटिलेटर सुविधा के साथ आइसीयू बिस्तर के लिए अधिकतम 15 हजार रुपए प्रतिदिन वसूल सकेंगे।

साथ ही यह भी कहा गया है कि 'बी' और 'सी' श्रेणी के शहरों में स्थित सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय उक्त दरों का क्रमशः 80 और 60 प्रतिशत शुल्क वसूल सकेंगे। स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित कोविड

चिकित्सालय के लिए यह शुल्क एक पैकेज है।

इस पैकेज में कोविड केर प्रावधान के अनुसार उपचार प्रदान किए जाने के लिए बिस्तर, भोजन, नर्सिंग केर, निगरानी और इमेजिंग सहित अन्य आवश्यक जांच, चिकित्सक देखभाल आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। को-मोर्बिड रोगियों का उपचार तथा अल्प अवधि की हीमो डायलिसिस की सुविधा भी पैकेज में शामिल है। यह दर निर्धारण बच्चों के उपचार पर भी लागू हैं हालांकि रेमडेसिविर, टोसिलीजूमाव व विभाग द्वारा समय-समय पर घोषित की गई अन्य दवा इस पैकेज में सम्मिलित नहीं है।

अस्पताल के आयुष्मान भारत योजना से आबद्ध होने की दशा में सीजेरियर प्रसव के व्यय की प्रतिपूर्ति आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के संबंध में अस्पताल से हो सकेगी। जो अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत आबद्ध नहीं है, वह आयुष्मान की दर पर कोविड मरीज़ों से शुल्क वसूल सकेंगे। □□

शेष.... एर्दोगान के राष्ट्रवाद से उपजे संकट

पहन कर जाती है।

एर्दोगान की इन नीतियों से तुर्की आने वाले पर्यटकों की संख्या में खासी कमी आई है। तुर्की के बदलते स्वरूप को लेकर कई मित्र राष्ट्रों से उसके रिश्ते ख़राब हुए हैं। वैश्विक संख्याओं में भी तुर्की की छवि ख़राब हुई है। वैश्विक संस्थाओं में भी तुर्की की छवि प्रभावित हुई है। पर्यटन से अरबों डॉलर कमाने वाले इस देश का पर्यटन उद्योग खस्ताहाल हो चला है। तुर्की में मुद्रा इतनी अस्थिर हो चुकी है कि उसकी कीमत हर रोज़ बदल रही है। महंगाई चरम पर है। तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा लीरा में डॉलर के मुकाबले गिरावट अपने निम्नतम डॉलर स्तर पर है। इस व्यापक गिरावट का एक सबसे प्रमुख कारण तुर्की के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज़ दर रखने की एर्दोगान की अपरंपरागत आर्थिक नीतियां हैं। इन आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि पेट्रोल पंपों और स्थानीय सरकारी कार्यालयों के बाहर सस्ते दामों में रोटी लेने के लिए कतारें लगती हैं। बेरोज़गारी चरम पर है। सालाना महंगाई दर 2002 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई के दौरान भी ब्याज़ दरों में कटौती को जारी रखा गया। इसे एर्दोगान ने इस्लाम के मूल्यों और आदर्शों से जोड़कर राष्ट्रवादी भावनाओं को उभार देने की कोशिश की।

एर्दोगान मीडिया को सरकारी तंत्र की तरह उपयोग करते हैं। कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है। डिजिटल और मनोरंजक माध्यम को भी अर्दोआन ने अपने राजनीतिक प्रचार का साधन बना लिया है। तुर्की के ऐतिहासिक ऑटोमन साम्राज्य के गठन पर बनी टीवी धारावाहिक 'दिरलिस

'ऐरेस्टर' को तुर्की के सरकारी टीवी पर प्रसारित करके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिशों की गई। इसी प्रकार तुर्की में सुल्तान सुलेमान के जीवन पर 'द मैनिफिसेंट सेंचुरी' नाम से एक टीवी नामक बना था। 16वीं शताब्दी में सुल्तान सुलेमान के नेतृत्व में आटोमन साम्राज्य शिखर पर था और इस नाटक में इसे ही दिखाया गया है। यह नाटक तुर्की के विविध समाज को बांटने वाला साबित हुआ। इन धारावाहिकों में तुर्की और इस्लाम के लिए धर्म युद्ध की तरह प्रचारित किया गया। ऐसे धारावाहिकों से देश में कट्टरता बढ़ रही है और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन मज़बूत हुए हैं। एर्दोगान पाकिस्तान जैसे देशों से रिश्ते मज़बूत करके कट्टरवादी ताक़तों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कारण तुर्की पर आतंकी हमलों के ख़तरे बढ़े हैं। एर्दोगान तुर्की के प्राचीन गैरव को लौटाने की बात कह कर खुद की नीतियों को निर्णयिक और बदलावकारी बताने का दावा कर रहे हैं। इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने की उनकी धन के चलते कई यूरोपियन देश उनसे खफा दिखते हैं। इसका असर निवेश पर पड़ सकता है रोज़गार प्रभावित हो सकता उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। बहरहाल आर्थिक मोर्चे पर तमाम नाकामियों के बाद भी एर्दोगान देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में खुद को प्रचारित करने के लिए तमाम तरह के राजनीतिक और धार्मिक हथकड़े अपना रहे हैं। धार्मिक शिक्षा के प्रसार से समाज विभाजित हो रहा है। एर्दोगान इस्लाम के सहारे चुनाव जीतने में तो लगातार सफल हो रहे हैं, लेकिन क्या वह तुर्की की अर्थव्यवस्था को ऊंचाईयों पर ले सकेंगे जिसकी सख़्त आवश्यकता है। □□

शेष.... मिस जैनेट रेनकिन...

उधेड़ना शुरू कर दिया, बहस बढ़ती गई, तो तनाव भी बढ़ता गया।

युद्ध समर्थक सांसदों की नज़रें उस अकेली महिला सांसद पर भी थीं इनका बोट तो हमें ही मिलेगा। तब उन महिला के दिमाग़ में कुछ अलग चल रहा था। कभी पिता की याद आती, जो अप्रवासी बढ़ी थे, तो कभी स्कूल शिक्षिका मां की याद। देश में शांति है, समझदारी है तभी तो लोगों ने ऐसी महिला को चुनकर भेजा हैं उन महिला के लिए ये सदन में आते ही सिर पर पड़ी मुसीबत थी। कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, लोग क्या कहेंगे? युद्ध का विरोध किया जाए, तो मुमकिन है लोग दोबारा न चुनें। युद्ध के पक्ष में बोट करने के लिए दोस्त और परिवार की ओर से भी दबाव पड़ रहा था। उनके भाई व विश्वासपात्र वेलिंगटन ने उनसे बहुमत के साथ रहने का आग्रह किया था, कहा था कि युद्ध के पक्ष में मतदान करना, वर्ना कैरियर खराब हो जाएगा।

फिर भी उन महिला सांसद को बार-बार लग रहा था कि यह एक व्यावसायिक युद्ध है। उन्हें संदेह था कि भविष्य के इतिहासकार क्या साबित करेंगे? हथियार उद्योग बहुत दबाव डाल रहा था। मन बार-बार कह रहा था, वह युद्ध आर्थिक फायदे के लिए होगा, लोकतंत्र के लिए नहीं।

फिर सदन में नाम पुकारा गया। तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, फिर एक पुकार हुई 'मिस जैनेट रेनकिन'। जिजासुओं ने उठ-उठाकर देखा। मौटना से पहली बार की रिपब्लिकन सांसद, सदन की पहली और अकेली महिला सिर झुकाए बैठी थीं। मन में शंकाएं।

शेष.... मंज़र परस-मंज़र

भारत में भी कोरोना वायरस के अत्याधिक संक्रामक 'ओमिक्रॉन'

वेरिएंट के कारण कोविड के मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जहां एक ओर संक्रमण फेलने की दर बढ़ रही है वहाँ चिंता की बात यह भी है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में 6 बड़े अस्पतालों के 750 डॉक्टर तथा स्वास्थ्य सहयोगी कोरोना से संक्रमित हैं। सबसे ज़्यादा एम्स प्रभावित हुआ है जहां वर्तमान में 350 रेजिडेंट डॉक्टर आइसोलेशन में हैं।

जहां महाराष्ट्र में कम से कम 364 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, वही बिहार में अब तक 550 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। अन्य राज्यों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 9 राज्यों 1700 से अधिक डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को कोविड-19 से प्रभावित पाया गया है। लम्बे समय से कोरोना ग्रस्त रोगियों का इलाज करते हुए डॉक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी मानसिक तथा शारीरिक थकान का

उमड़ रही थीं। फिर आवाज आई, 'मिस रैनकिन'। तब रैनकिन घबराई हुई सी उठीं और साहस और दृढ़ता के साथ कहा, 'मैं अपने देश के साथ खड़ी होना चाहती हूं, लेकिन मैं युद्ध के लिए बोट नहीं कर सकती।'

यह अमेरिकी सदन में पहली महिला का पहला उद्बोधन था। युद्ध के पक्षधर शोर मचाने लगे, 'बोट करो, बोट करो, पर नैरकिन ने फिर कहा, 'नहीं, और सभागार से बाहर चली गई। दूसरे दिन पूरे देश में चर्चा थी कि सदन की अकेली महिला ने युद्ध के खिलाफ़ बोट दिया। युद्ध के खिलाफ़ बोट करने वालों में पुरुष भी शामिल थे, पर ज़्यादा चर्चा जेनेट रैनकिन की ही थी। वह अपने देश में शांति की सबसे बड़ी पैरोकार बन गई। वह भारत भी आई थीं और महात्मा गांधी से प्रभावित थीं। वह 1940 में फिर कांग्रेस में लौटीं, तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। पर्ल हार्बर पर हमला हो चुका था, पूरा अमेरिका युद्ध में कूदने का आहवान कर रहा था, तब भी शांतिप्रिय रैनकिन ने युद्ध के खिलाफ़ बोट किया था।

उनके रोकने से अमेरिका नहीं रुका और दुनिया ने पहला परमाणु हमला झेला। आज भी जब अमेरिका कहीं हमले के लिए तैयार होता तो वहाँ जेनेट रैनकिन की याद ज़रूर आती है कि वह खड़ी होंगी और युद्ध के खिलाफ़ बोट करेंगी। वह 7 नवंबर, 1916 को पहली बार कांग्रेस के लिए चुनी गई थीं। वह दुनिया को आज भी प्रेरित करती हैं कि धारा के विपरीत खड़ा होना और अस

मंज़र पस-मंज़र

मीम.सीन.जीम

दहेज पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार महामारी में चुनाव बहुत महंगी पड़ सकती है ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल

दहेज पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग को भी दहेज बताते हुए अपराध माना है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, दहेज शब्द को एक व्यापक अर्थ के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, ताकि एक महिला से किसी भी मांग को शामिल किया जा सके, चाहे संपत्ति के संबंध में हो या किसी भी तरह की मूल्यवान चीज। निचली अदालत ने इस मामले में मृतक के पति और ससुर को

हाईकोर्ट के पैनसले पर असहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि विधायिका के इरादे को विफल करने वाली कानून के किसी प्रावधान की व्याख्या को इस पक्ष में छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह सामाजिक बुराई की ख़त्म करने के लिए कानून के माध्यम से हासिल की जाने वाली वस्तु को बढ़ावा न दे। धारा-304बी के प्रावधान समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने व जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हैं। एक अन्य दहेज प्रताड़ना में आत्महत्या मामले में सास की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एक महिला ही दूसरी महिला को न बचाए तो यह गंभीर अपराध है। कोर्ट ने सास को दोषी ठहराते हुए तीन माह की सज़ा सुनाई। पीठ ने कहा, यह बेहद भयावह स्थिति है जब एक महिला अपनी ही बहू पर इस कदर क्रूरता करे कि वह आत्महत्या का कदम उठा ले। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री अधिकारियों को शीर्ष अदालत के नियमों को अच्छी तरह जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत का आदेश रद्द किये जाने के खिलाफ़

आईपीएस की धारा-304-बी (दहेज हत्या), आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज उत्पीड़न के तहत दोषी ठहराया था। यह पाया गया, आरोपी मरने वाली महिला से घर बनाने के लिए पैसे की मांग कर रहा था, जो उसके परिवार के सदस्य देने में असमर्थ थे। इसके लेकर महिला को लगातार परेशान किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस फैसले के खिलाफ़ दायर अपील पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग को दहेज की मांग के रूप

ज़खरी ऐलान

आपकी खरीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रकम भेजने की कृपा करें।

रकम भेजने के तरीके:-

① मनीआर्ड द्वारा ② Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION
③ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate IFS Code: SBIN0001187

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शक्तील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, कासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, नं. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173

में नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि विधायिका के इरादे को विफल करने वाली कानून के किसी प्रावधान की व्याख्या को इस पक्ष में छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह सामाजिक बुराई की ख़त्म करने के लिए कानून के माध्यम से हासिल की जाने वाली वस्तु को बढ़ावा न दे। धारा-304बी के प्रावधान समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने व जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हैं। एक अन्य दहेज प्रताड़ना में आत्महत्या मामले में सास की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एक महिला ही दूसरी महिला को न बचाए तो यह गंभीर अपराध है। कोर्ट ने सास को दोषी ठहराते हुए तीन माह की सज़ा सुनाई। पीठ ने कहा, यह बेहद भयावह स्थिति है जब एक महिला अपनी ही बहू पर इस कदर क्रूरता करे कि वह आत्महत्या का कदम उठा ले। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री अधिकारियों को शीर्ष अदालत के नियमों को अच्छी तरह जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत का आदेश रद्द किये जाने के खिलाफ़

दायर विशेष अनुमति याचिका के साथ आत्मसमर्पण से छूट की मांग करने वाली अर्जी दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

महामारी में चुनाव

चुनाव आयोग की ओर से पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अन्तिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही यह भी होते हैं और पारंपरिक तौर तरीकों में बदलाव किये जाते हैं तो अमूमन आर्थिक तौर पर मज़बूत और बड़ी पार्टियां फायदे में होती हैं। उनके लिए प्रचार के नए तौर तरीके निकालना और अपनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों ने चुनाव आयोग से अपील भी की है कि डिजिटल माध्यमों में सभी दलों की उपयुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएं। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस दिशा में क्या कदम उठाता है। इसी संदर्भ में यूपी में सात चरणों का लंबा चौड़ा चुनाव कार्यक्रम भी ध्यान खींचता है। 2017 में भी वहां सात चरणों में ही चुनाव हुए थे, लेकिन तब कोरोना का कोई प्रकोप नहीं था। मणिपुर की तरह चुनाव पूर्व हिंसा का भी कोई मामला फिलहाल यूपी में नहीं दिख रहा। ऐसे में सात चरणों तक चुनाव प्रक्रिया

कोरोना गाइडलाइंस जारी करते हुए इन्हें स्वीकार करने की बात कही है लेकिन इन हालात में सभी दलों को लेवल प्लेइंग मुहैया कराना भी चुनाव आयोग का ही दायित्व है। जब भी ऐसी असामान्य स्थितियों में चुनाव होते हैं और पारंपरिक तौर तरीकों में बदलाव किये जाते हैं तो अमूमन आर्थिक तौर पर मज़बूत और बड़ी पार्टियां फायदे में होती हैं। उनके लिए प्रचार के नए तौर तरीके निकालना और अपनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों ने चुनाव आयोग से अपील भी की है कि डिजिटल माध्यमों में सभी दलों की उपयुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस दिशा में क्या कदम उठाता है। इसी संदर्भ में यूपी में सात चरणों का लंबा चौड़ा चुनाव कार्यक्रम भी ध्यान खींचता है।

अगले दौर को भी निर्णयक रूप से प्रभावित कर सकती है।

बहुत महंगी पड़ सकती है ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल

दुनिया भर में वही हो रहा है जिसका डर था - कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' के चलते संक्रमण में तेजी की वजह से कई देशों में हालात बिगड़ने लगे हैं। अमरीका और इंग्लैंड में एक बार फिर कोरोना ने हाल बेहाल कर दिया है। अब

बाकी पेज 11 पर

उप्र० : 15.2 करोड़ वोटर चुनेंगे 403 विधायक

यूपी चुनाव का परिणाम तय करेगा कि 2024 में किसकी सरकार होगी, भाजपा या गठबंधन दलों की। प्रदेश में सात चरणों में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए 14 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में 15.02 करोड़ मतदाता कुल 403 विधायक चुनेंगे। इसके लिए 1.74 लाख मतदाता केन्द्र बनाए गए हैं।

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। शहरों में राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित लगी होर्डिंग्स, बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे हैं। उधर, सभी सरकारी बेबसाइट से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की फोटो भी हटाए जाने के निर्देश हैं। चुनाव आयोग पेड न्यूज़ पर भी नज़र रखेगा। अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो चुनाव आयोग के विजिल एप पर इसकी शिकायत की जा सकती है।

सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जल्द नियुक्त होंगे पर्यवेक्षक

आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए दूसरे राज्यों से आईएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती चुनाव आयोग करेगा।

चुनावी खर्च के लिए उम्मीदवारों को खोलना होगा अलग खाता

उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए अलग से खाता खोलना होगा। इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। जो भी चुनावी खर्च होगा, उसे इसी खाते से देना होगा। 20 हज़ार रुपये से अधिक नक़दी खर्च नहीं कर सकेंगे।

अपने प्रिय अखबार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगआॉन करें:

www.aljamiat.in — www.jahazimedia.com

Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

खरीदारी चन्दा

वार्षिक Rs.130/-

6 महीने के लिए Rs.70/-

एक प्रति Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक

शांति मिशन

1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455